RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ... सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-08, अंक - 47 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 10 सितम्बर 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

बीके शिवानी दीदी

न दवा ना दारू कुछ भी असली नहीं...राम-राज या राम भरोसे राज...?

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

सागर। वैसे तो शराब शरीर के लिए हानिकारक है ही और पीने वालों के लिए न केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी गहरा आघात पहुंचाती है। लेकिन फिर भी शराब पीने और पिलाने का चलन आदिकाल से ही चला आ रहा है। वही शराब शासन के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है और सरकार लाख कोशिशें और शराब बंदी की व्यापक मांग के बावजूद इसे बंद नहीं कर पाई। यही कारण है कि, लॉकडाउन के बाद जब स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगी तो सरकार ने मंदिरों से पहले मदिरालय खोलने की स्वीकृति दी थी।

हाल ही में सागर जिले की बंडा तहसील और शाहगंढ़ के आसपास ग्रामीण इलाकों में जहरीली शराब पीने से अब तक करीब 25 से अधिक मौत और 130 से अधिक लोगों के अस्पताल के भर्ती होने की घटना के बाद शासन और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उक्त आकडा भी सरकार के अनुसार है। इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में यह पहली बार नहीं हुई है पूर्व में भी इस प्रकार की कई घटनाएं घटित हो चुकी है। जिसमें जनवरी 2021 में मुरैना और बामोर में भी जहरीली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2020 में उज्जैन शहर के मजदूर बाहुल्य इलाके में भी 14 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए थे। इसके साथ ही देश भर में समय-समय पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तभी रेंगती है जब घटना बड़ी होती है, मौतों की संख्या अधिक होती है। लेकिन विडंबना देखिए हर घटना के बाद जांच के नाम पर कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों के निलंबन और प्रकरण दर्ज होता है, मामला लोगों की स्मृति से गायब होता है तब तक फिर एक नया मामला सामने आ जाता है। पहले शराब देशी, महुआ और कुछ अनाजों के जरिए प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती थी लेकिन अब कम लागत और ज्यादा कमाई के चक्कर में घातक रसायनों के जरिए बनाई जाने लगी जो प्रायः जहरीली हो जाती है। हमारे देश में शराब को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताए जाने के बावजूद उसका चलन तो प्रतिदिन बढ़ता जा ही जा रहा है। लेकिन गुणवत्ता लगातार गिरती ही जा रही है। अवैध शराब व नकली होलोग्राम की शराब, बल्क से बनाई जाने वाली शराब और शराब का अवैध भंडारण और परिवहन आम बात हो गई है। समय-समय पर पुलिसिया कार्रवाई भी होती है लेकिन मामला रफा-दफा हो जाता है और मामला कैसे रफा-दफा होता है यह किसी से छिपा नहीं है।

माही की गूंज भी लगातार अवैध शराब, नकली एवं बाहरी शराब को लेकर शासन-प्रशासन को आगाह करता रहता है। लेकिन बावजूद इसके शराब का यह अवैध कारोबार न केवल झाबुआ जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बदस्तूर जारी है।

न दवा सुरक्षित न दारू सुरक्षित

मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 में छिंदवाड़ा जिले और आसपास के क्षेत्रों में जहां डायथनिल ग्लाइकोल (डीईजी) से दूषित सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई थी। दवा का नाम कोल्ड्रफ सिरप था जिसे श्रीसंस फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया था और डॉक्टर अधिक कमीशन के चक्कर में वही सिरप बच्चों के लिए लिखते थे। जिसके बाद प्रशासन जागा और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। यही नहीं झाबुआ जिले में कुएं के पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रातों-रात कुआं खाली करवा दिया और उसमें दूसरे नलकूप का पानी भर दिया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने उस पानी की जांच करवा कर क्लीन चिट पा ली और प्रशासन अपनी गलती छुपाने में कामयाब रहा। घटना को दूषित खाद्य पदार्थ से जोड़ कर मामले की इतिश्री कर ली गई। यानी मध्यप्रदेश में न पानी सुरक्षित है, न दवा सुरक्षित है और न ही दारू सुरक्षित है। इसलिए यह कहना मुश्किल हो रहा है कि, यहा राम-राज या राम भरोसे राज....?

माही की गूंज, छात्रों की गूंज और झूठ की गूंज...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

जिले का प्रमुख साप्ताहिक अखबार माही की गूंज जिले के साथ ही देश और प्रदेश की खबरों को प्रमुखता से उठाता आ रहा है। जिसके बाद गूंज की गूंज देश भर में गुजने लगी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज के नाम से इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम सितंबर के शुरुआती दिनों में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी जिसके चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर 19 सितंबर कर दिया गया है। हालांकि कार्यक्रम की प्रशासनिक अनुमति अभी भी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक नेहरू स्टेडियम में अनुमति न मिलने की स्थिति में अन्य मैदानो का विकल्प प्रशासन के सामने रखा है। फिलहाल छात्रों की गूंज कार्यक्रम को प्रशासनिक अनुमति का इंतजार है लेकिन कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं की तुलना शादी में रूठे हुए फूफा से की है और विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना को झूठ की गूंज करार दिया है। यानी हर तरफ गूंज की गूंज है।

तेज रफ्तार थारः 10 से ज्यादा कारों को मारी टक्कर

भोपाल। राजधानी भोपाल की फार्चून सोम्या हेरिटेज कॉलोनी में बुधवार देर रात तेज रफ्तार थार ने खड़ी 10 से ज्यादा कारों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया। कई लोग हादसे में बाल-बाल बच गए।

बताया जा रहा है कि क्रमांक एमपी 04 वाईजेड 1173 वाली थार तेज रफ्तार से कॉलोनी में आई। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और रास्ते में खड़ी कारों को टक्कर मारता चला गया। इसके बाद थार कॉलोनी के गेट से भी टकरा गई और गेट को नुकसान पहुंचाकर चालक वाहन सहित भाग गया।

हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन 10 से ज्यादा कारों को नुकसान पहुंचा है। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना मिलने पर मिसरोद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मतदाता सूची में तीन अफगान नागरिक

रांची, एजेंसी। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की प्रारंभिक मतदाता सूची में तीन अफगान नागरिकों के नाम सामने आए हैं। मामला सामने आने के बाद चुनाव अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों के अनुसार आसिल खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम के नाम मतदान केंद्र क्रमांक 286 की सूची में दर्ज थे। दस्तावेजों की जांच में संदेह होने पर तीनों को नोटिस जारी कर नागरिकता से जुड़े कागजात मांगे गए, लेकिन वे वैध दस्तावेज नहीं दे सके। इसके बाद पासपोर्ट की जांच में उनके अफगान नागरिक होने की जानकारी सामने आई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि तीन विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। इनमें एक की विदेशी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो की जांच जारी है। तीनों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब यह पता लगाया जा रहा है कि विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में किस तरह शामिल हुए और इसमें किसकी भूमिका रही। अधिकारियों ने तीनों के परिवार के अन्य सदस्यों के दस्तावेजों की भी जांच के निर्देश दिए हैं।

पूर्व मुख्य सचिव की घर में मौत

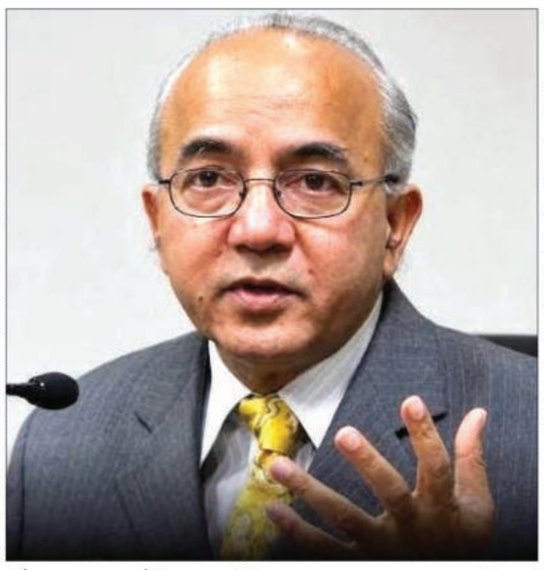

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और 1975 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश मेहता की 6 सितंबर को नोएडा सेक्टर-82 स्थित उनके घर में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जिक्र होने की बात सामने आई है।

बताया गया है कि घटना के समय राकेश मेहता घर में अकेले थे। उनकी पत्नी छोटे बेटे से मिलने देहरादून गई हुई थीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे खोलकर पुलिस अंदर गई और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से मिले कथित सुसाइड नोट को भी जांच में शामिल किया है।

राकेश मेहता ने वर्ष 2007 में दिल्ली के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं। वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के दौरान भी वे मुख्य सचिव के पद पर थे। उनके कार्यकाल में दिल्ली में परिवहन और दूसरी जरूरी सुविधाओं से जुड़े कई काम हुए।

तीन दशक से ज्यादा लंबे प्रशासनिक जीवन के बाद वे नवंबर 2010 में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे और दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली।

तमिलनाडु में सरकार गिराने की तैयारी

च े न्ना ई ं , एजेंसी।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने की कोशिश तेज हो गई है। अन्नाद्रमुक ने प्रमुख विपक्षी दल द्रमुक को भी अपने साथ आने का न्योता दिया है। पार्टी का कहना है कि टीवीके के विरोध में दूसरी नई पार्टियां भी उसके साथ जुड़ सकती हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री एडापड्डी के. पलनीस्वामी से जब टीवीके के खिलाफ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक टीवीके के खिलाफ है और दूसरी पार्टियां साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है। उन्होंने द्रमुक को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वह भी इस गठबंधन में शामिल होगी।

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। अन्नाद्रमुक के छह विधायक विजय की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि बाकी विधायकों के बीच भी गुटबाजी की स्थिति सामने आई थी। इसी के बाद विपक्षी दलों के बीच नए समीकरण बनाने की चर्चा तेज हुई है।

द्रमुक नेता आरएस भारती पहले दोनों दलों के साथ आने की संभावना से इनकार कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में द्रमुक और अन्नाद्रमुक साथ आते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अगस्त में कहा था कि उनकी पार्टी फिर से मजबूत होकर जनता का समर्थन हासिल करने में सक्षम है।

छात्रावास संकट : 70 हजार विद्यार्थी, 7 हजार सीटें

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में हर वर्ष 70 हजार से अधिक विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, लेकिन छात्रावासों में केवल करीब 7 हजार सीटें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध 77 महाविद्यालयों में से लगभग 20 में ही छात्रावास सुविधा है, जबकि 57 महाविद्यालयों के पास अपना छात्रावास नहीं है।

छात्रावासों की कमी को देखते हुए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर छात्रावास विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने सभी महाविद्यालयों को 10 दिनों के भीतर छात्रावास निर्माण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार अधिकांश महाविद्यालयों के पास निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि नई योजनाओं से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को परिसर में ही आवास की सुविधा मिल सकेगी।

इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी चिंता जता चुका है। आयोग ने दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

हसीना को लाकर फांसी की सजा दिलाने पर अड़ा बांग्लादेश

ढाका, एजेंसी।

बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि सरकार हसीना का भारत से प्रत्यर्पण चाहती है और बांग्लादेश लौटने पर उन्हें अदालत के फैसले के अनुसार मौत की सजा का सामना करना होगा।

जाहेद ने कहा कि हसीना की वापसी के लिए भारत से प्रत्यर्पण की मांग किसी दबाव की रणनीति का हिस्सा नहीं है। सरकार चाहती है कि वह खुद बांग्लादेश लौटें या कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी।

अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद हसीना भारत आ गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार पहले भी भारत से उनका प्रत्यर्पण करने की मांग कर चुकी है। भारत ने कहा है कि, उसे हसीना के प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध मिला है और उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि हसीना की वापसी का उद्देश्य अदालत के फैसले को लागू करना है। हालांकि, उन्हें भारत से बांग्लादेश भेजने का अंतिम फैसला भारत के रुख और दोनों देशों के बीच चल रही प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

घटिया निर्माण को लेकर दर्ज करवाई शिकायत, रात के अंधेरे में बिना सरिए के किया जा रहा पुलिया निर्माण

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

पूरे देश के अलग-अलग क्षेत्रों से कही पुल तो कही भवन गिरने ओर जर्जर होने की खबरे आती है। बड़ी घटना होने पर कार्रवाई की जाती है। निर्माण एजेंसी के लापरवाह अधिकारियों पर गाज भी गिरती है लेकिन ये सब होता किसी बड़े हादसे के बाद। इससे पहले जब निर्माण होता है तो उसकी देख-रेख में गंभीर लापरवाही ओर शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं देने के कारण ठेकेदार मनमाने ढंग से काम कर के निकल जाते हैं। कमीशन के खेल में हर कोई निर्माण एजेंसी को भरपूर सहयोग करते है ओर घटिया निर्माण को देख कर अनदेखा कर देते है।

मामला पेटलावद विकासखंड की ग्राम पंचायत बैंगनबड़ी का है, जहा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा डाबड़ी फंटे से बैंगनबड़ी मार्ग तक लगभग डेढ़ किलोमीटर का मार्ग बनाया जाना है, जिसकी लागत डेढ़ करोड़ के लगभग बताई जा रही है। विभाग ने उक्त मार्ग की जो लागत तय की थी उससे लगभग 23 प्रतिशत कम में गुजरात की एक कम्पनी ने रोड निर्माण का ठेका लिया है। रोड निर्माण के दौरान एक पुलिया बनाया जाना है जिसका निर्माण वर्तमान में जारी है। पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने घटिया कार्य की शिकायत

विभाग ओर कार्य के उपयंत्री चौहान को भी की। लेकिन उपयंत्री द्वारा कार्य में सुधार के आश्वासन देने की बजाए, शिकायतकर्ता को कार्य पंचायत का नहीं विभाग का होने की बात कहते हुए दिन के उजाले में काम करने की बात कही। जिसे सब देख रहे है काम कैसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद से ठेकेदार ने पुलिए का काम रात में भी शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता सुखराम द्वारा रात में चल रहे कार्य में भारी लापरवाही देखकर निर्माण कार्य के ठेकेदार से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई ओर रात में कार्य जारी रखा गया है। सुखराम ने बताया कि, ठेकेदार द्वारा रात में पुलिया निर्माण किया जा रहा जिसमें घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है ओर सरियों का उपयोग नाम मात्र का किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि, पुलिये के निर्माण में महत्वपूर्ण अर्थ वर्क के दौरान विभाग के जवाबदार लोग मौके पर नहीं हैं और उसी का फायदा उठा कर रात में काम किया जा रहा है। ग्रामीण सुखराम द्वारा मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई गई।

शिकायतकर्ता पर बनाया जा रहा दबाओ, उपयंत्री ने कहा कार्य ड्राइंग के अनुसार

शिकायत के बाद कार्य की एजेंसी ओर उपयंत्री द्वारा शिकायतकर्ता पर शिकायत बंद करने का दबाओ बनाया जा रहा है ताकि मामले को दबाया जा सके । मामले में कार्य के उपयंत्री चौहान ने बताया कि, कार्य ड्राइंग के अनुसार किया जा रहा है। किसी प्रकार का घटिया निर्माण नहीं है। वर्तमान में पुलिया के खुदाई कार्य मे सिर्फ जो हार्ड रोक खुदाई की गई है उसका लेवल कार्य किया गया है, अभी पुलिया का वास्तविक कार्य प्रारंभ नही किया गया है , ओर विडियो में जो गड्ढा दिखाई दे रहा है वो ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको एकत्रित कर बाहर निकालने के लिए गड्ढा किया है, जिसमे पानी निकालने की मोटर लगी हुई है। रात में किए जा रहे कार्य को लेकर उपयंत्री ने कहा, ठेकेदार 24 घंटे कार्य कर सकता है अगर ठेकेदार द्वारा कोई लापरवाही की जा रही है तो उसकी जांच भी की जाएगी।

राहुल का जनता दरबार, उमड़ी भीड

रायबरेली।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के अंतिम दिन बुधवार को भुएमऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया गया। सुबह करीब नौ बजे शुरू हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। गेस्ट हाउस के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी रही और सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को एक-एक कर अंदर भेजा गया।

जनता दरबार में आम नागरिकों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी से मुलाकात कर स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याएं रखीं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव अखिलेश माही ने कारगिल युद्ध में शहीद रायबरेली के राजेंद्र यादव के नाम पर स्मारक और चौराहा बनवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने इस मांग पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।

महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। रायबरेली महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी सिन्हा ने उन्हें राखी बांधकर तिलक लगाया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने ज्ञापन सौंपकर मुंशीगंज शहीद स्मारक का अधूरा सौंदर्यीकरण कार्य पूरा कराने की मांग की।

इस दौरान सर्राफा कारोबारियों से हुई बैठक का मुद्दा भी चर्चा में रहा। कारोबारियों ने सोने-चांदी के कारोबार में आई गिरावट और जीएसटी से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। राहुल गांधी ने उनकी समस्याओं को संसद में उठाने का भरोसा दिया।

राहुल गांधी अपने दौरे के अंतिम दिन सांसद निधि से करीब तीन करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएल चौपड़ा ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिटोल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।

सीएमएचओ ने प्रसूति पश्चात वार्ड का निरीक्षण कर वहां भर्ती महिलाओं से बातचीत की और उपचार व अन्य सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने माताओं को नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के वार्डों और परिसर में साफ-सफाई की स्थिति भी देखी। अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित सफाई रखने तथा जहां आवश्यक हो वहां व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सक डॉ. विजेंद्र कुमार मेरावत ने स्वास्थ्य केंद्र में पानी की समस्या की जानकारी दी। इस पर सीएमएचओ ने तत्काल स्थानीय सरपंच से फोन पर चर्चा कर समस्या का जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए।

पंचायत उपचुनाव के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त

माही की गूंज, झाबुआ।

पंचायत उपचुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रवार सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं की निगरानी और आवश्यक समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कृषि विस्तार अधिकारी पुनमचंद थंदर को पलासडोर, परवाड़ा, दौलतपुरा और रम्भापुर के मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी रूपसिंह बामनिया को कंजावानी और समोई के मतदान केंद्र सौंपे गए हैं। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका बघेल के अधीन समोई, जुनागांव, सनोड और छगोला के मतदान केंद्र रहेंगे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र मावी को अंधारवड़, खेड़ा अंधारवड़, सनोड और अंधारखड़ क्षेत्र के मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पंकज सांवले को मोरडिया, छयन खुर्द, माछलिया झिर, ढढोरी, मोरडुंडिया, निवास फलिया और कड़िया क्षेत्र के मतदान केंद्र सौंपे गए हैं।

जिला विपणन संघ की अधिकारी अमिता मोर्य को सरदारपुरा, चोरमांडली, चारमाली, चुई और पटेल फलिया चुई के मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी मिली है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. कलमसिंह बारिया को पुवाला, भूतखेड़ी और बन क्षेत्र के मतदान केंद्र सौंपे गए हैं।

जिला खनि अधिकारी जवानसिंह भिंडे को भूरीमाटी, मालिपुरा, डुंगरा, आम्बाकुआ, धामनीकटारा और भोडली क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार को मातासुला छोटा, मातासुला बड़ा और छायन सेमलखेड़ी क्षेत्र के मतदान केंद्र सौंपे गए हैं।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्यपालन यंत्री मनोहर वसुनिया को सारसवाट, परतली, ढोलियावड़, छापरखण्डा और भोरकुंडिया क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। उप संचालक कृषि सज्जनसिंह चौहान को डिग्गी, कैथोलिया, अगेरा, डुंगरी, मोहनपुरा भुरका, चुलियाबड़ी और बेडखिया फलिया के मतदान केंद्रों का दायित्व दिया गया है।

सहायक संचालक उद्यानिकी मोहनसिंह मुजाल्दा, ग्रामीण सड़क प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवीण अहिरवार और खाद्य एवं औषधि निरीक्षक गीतम पटोदिया को वैकल्पिक सेक्टर अधिकारी रखा गया है। सभी अधिकारियों को अपने-अपने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबल कार्ड निष्क्रिय

माही की गूंज, झाबुआ।

संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए समग्र ई-केवाईसी कराना जरूरी किया गया है। निर्धारित समय सीमा में ई-केवाईसी पूरी नहीं कराने पर जिले के 27 हजार 771 श्रमिकों के संबल कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। विभाग के अनुसार श्रमिकों को 13 जून 2026 तक ई-केवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिकों ने तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके बाद संबंधित संबल कार्ड को पोर्टल पर अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरी कराने के बाद संबल कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ई-केवाईसी पूरी होते ही कार्ड अपने आप सक्रिय हो जाएगा और श्रमिक योजना के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

विभाग ने सभी पात्र श्रमिकों से जल्द से जल्द समग्र ई-केवाईसी कराने की अपील की है, ताकि वे संबल योजना के लाभों से वंचित न हों।

शिक्षक दिवस पर सम्मानित प्राचार्य की दो दिन बाद ही एसडीएम के औचक निरीक्षण में खुली पोल

निरीक्षण में अटैचमेंट का मामला भी आया सामने, साहब के पास दो संकुल का चार्ज

माही की गूंज, पेटलावद।

शिक्षक दिवस को कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने थोक में शिक्षक सम्मान दिया। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में नगर की विभिन्न स्कूल प्राचार्यों और खण्ड शिक्षा अधिकारी को मंचो पर स्थान देने के साथ सम्मानित भी किया गया। मंचो से सम्मानित इन प्राचार्यों ने अपने उद्बोधनों में खुद की तारीफ में बड़े-बड़े कसीदे पढ़े और ऐसा बताया गया कि, हमारा मैनेजमेंट पूरे जिले में नम्बर वन है। परन्तु मात्र दो दिन बाद ही इनकी कलई खुल गई। कुल मिलाकर जब कोई निरीक्षण प्रायोजित हो और सभी को पता हो तो ये विद्यालय प्रमुख आने वाले अतिथियों और निरीक्षणकर्ता अधिकारी को केवल हरा-हरा दिखाते हैं और अपनी कमियों को हार-फूलो से ढक देते हैं, और फिर सम्मान पा जाते हैं। पर जब औचक निरीक्षण होता हैं तो सब पोल खुल जाती हैं और फिर अधिकारी के सामने सर झुका कर खड़े हो जाते हैं। वर्तमान में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने जिले की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत है और उसी अनुरूप उनके द्वारा गठित विभिन्न विभागों की टीम को विद्यालयीन संस्थाओं का औचक निरीक्षण का दायित्व सौंपा है। उसी अनुरूप पेटलावद नगर की विभिन्न स्कूल संस्थाओं का औचक निरीक्षण नवागत एसडीएम रितिका पाटीदार ने किया जहां संस्थाओं की पोल खुली है।

ओचक निरीक्षण करती एसडीएम रितिका पाटीदार ओर सर झुकाए खड़े जवाबदार।

सम्मानित शिक्षकों की पोल

शिक्षक दिवस के मात्र दो दिन बाद ही अनुविभागीय अधिकारी रितिका पाटीदार द्वारा नगर की संस्थाओं का निरीक्षण किया। तो वो ही ढांक के तीन पात याने जो प्राचार्य कल तक हरा-हरा दिखाते आ रहे थे, वो आज मैडम के निरीक्षण में बगले झाँकते नजर आए। सरकार के बड़े-बड़े दावे सांदीपनी विद्यालय के लिए किए जाते है पर जमीनी स्तर पर जहां अभी त्रैमासिक परीक्षा आयोजित हो रही है वहां परीक्षा में छात्रों की संख्या कम नजर आने पर एसडीएम ने प्राचार्य पूरालाल चौहान को लताड़ लगाई और असंतोष जताया। आखिर इस संस्था का विगत वर्ष में 100 प्रतिशत रिजल्ट देने पर भी प्रश्न खड़ा होता हैं कि जिस शाला के बच्चे त्रैमासिक परीक्षा में रुचि नहीं रखते वो कैसे वार्षिक में शत-प्रतिशत उत्तीर्ण हो जाते है। वहीं हम नगर की एक अन्य संस्था हायर सेकंडरी कन्या शाला स्कूल में एसडीएम मैडम को शिक्षक ही अनुपस्थित मिले। जो प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद दो दिन पहले तक सम्मानित होकर स्कूल की तारीफ में मंचो से कसीदे पढ़ रहे थे, वो निरीक्षण के दोरान मुंह लटकाए खड़े थे। एसडीएम ने अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अगर इन प्राचार्य महोदय की बात करे तो कई बार इनके कार्यकाल में कई ऐसे मामले देखे गए कि, कभी बच्चे रोड पर आंदोलन करने को मजबूर हुए, तो कभी बच्चे अपनी दर्द भरी दास्तां राज्यपाल के सामने सुनाते नजर आए हैं। यूं कहे कि, ये एक विद्यालय के चार्ज को नहीं सम्हाल पा रहे हैं वो पूरी कन्या संकुल का प्रभार कैसे सम्हालते होंगे?

ताजुब्ब की बात ये है कि, इसके बाद भी कन्या संकुल के अतिरिक्त दूसरे करवड़ संकुल का प्रभार भी जुगाड लगा कर ले आए हैं जो पेटलावद से 15 से 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब साहब की एक टांग पेटलावद तो दूसरी करवड़ संकुल में है। वैसे साहब की मंशा तो पेटलावद खण्ड शिक्षा अधिकारी की कुर्सी की भी है पर विभागीय जांच में दोषी होने के कारण व दो वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित है और फिर वर्तमान में भी खुद के द्वारा विभाग को गुमराह कर वेतन वृद्धि भुगतान करवाने में कामयाब भी हो गए थे परंतु विभाग के आला अधिकारी के सामने ये चालाकी काम नहीं आई और पकड़े भी गए। मामला मीडिया में आने के बाद बीईओ पर गाज गिरी ओर उनको हटाया गया लेकिन वो भी न्यायालय से स्टे लेकर वापस आ गए। दोपहर तक काली पट्टी ताक में रखकर विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमो में सम्मान लेने पुरी संस्था के शिक्षक, साहब के पीछे दौड़े चले गए।

वहीं नगर की एक अन्य संस्था मिडिल स्कूल गढ़ी पर भी एसडीएम पहुंची जहां उन्होंने एक ही कक्ष जहां कक्षा 1 से 3 के बच्चों को पाकर प्रधान अध्यापिका से शिक्षक के बारे में जानकारी मांगी तो बताया कि, उक्त शिक्षक को कम्प्यूटर कार्य के लिए कन्या शाला अटैच किया गया है जो दोपहर पश्चात वहीं जाते हैं। उक्त अनुपस्थित शिक्षक को अपने मूल कार्य पर रहने के साथ खेल मैदान को सुधारने व साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए गए ।

एक हाथ में काली पट्टी दूसरे हाथ में सम्मान

वही कन्या स्कूल के शिक्षको ने अन्य स्कूलों के शिक्षकों की तरह शिक्षक दिवस पर काली पट्टी धारण कर मिलने वाले सम्मान का विरोध सोशल मीडिया पर छाये रहा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एसडीएम के अचेक निरीक्षण के बाद मामला इस बात को भी लेकर चर्चा में है कि, केवल शिक्षक होना ही सम्मान का मापदंड है क्या? उसके कार्यों से तुलना के बाद सम्मान की श्रेणी तय नहीं होनी चाहिए?

वही एसडीएम रितिका पाटीदार के अचेक निरीक्षण के बाद पूरे विकास खंड में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि स्कूलों में भारी अनियमितता की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ओर भी चिंताजनक है जहां शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर मध्यान भोजन में बड़ी अनियमितता है। बिना जानकारी के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों का दौरा किया जाए तो पूरी तरह चरमरा चुकी शिक्षा व्यवस्था ओर व्यवस्था संभालने के लिए तैनात अधिकारीयों की पोल खुल जाएगी।

मेघनगर में कलेक्टर की सूझबूझ ने जीता जनआंदोलन का भरोसा, अब प्रदूषण के समाधान और जवाबदेही पर सवाल

माही की गूंज, धर्मेंद्र पंचाल।

मेघनगर में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर उभरा जनआक्रोश अब केवल एक स्थानीय आंदोलन का विषय नहीं रह गया है। यह मामला पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, कृषि, जलस्त्रोतों और प्रशासनिक निगरानी की कार्यप्रणाली से जुड़े कई गंभीर सवाल सामने ला रहा है। ऐसे संवेदनशील समय में झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट का मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से संवाद करना और जनसुनवाई को मेघनगर में ही आयोजित करने का निर्णय प्रशासनिक सूझबूझ और परिस्थितियों की गंभीरता को समझने वाला एक कदम कहा जा सकता है।

किसी भी जनआंदोलन के दौरान प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती होती है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना और जनता की वास्तविक शिकायतों को सुनना। मेघनगर में प्रशासन ने टकराव की स्थिति को बढ़ाने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया। कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी तथा स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई की पहल से तत्काल तनाव कम करने में मदद मिली। यह संदेश भी गया कि, प्रशासन जनता की शिकायतों को केवल जिला मुख्यालय की फाइलों तक सीमित नहीं रखना चाहता।

लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या जनसुनवाई के बाद भी वही समस्याएं बनी रहती हैं, तो जनता का भरोसा कितने समय तक कायम रहेगा...? जनआंदोलन का शांत होना प्रशासन की तत्काल सफलता हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान के बिना इसे समस्या का अंत नहीं माना जा सकता।

ग्रामीणों द्वारा प्रदूषण पानी, खेती और स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इन शिकायतों को केवल भावनात्मक या राजनीतिक मुद्दा मानकर खारिज करना भी गलत होगा। इसलिए पानी और मिट्टी के नमूनों की स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक जांच, फसलों और पशुधन पर संभावित प्रभाव का आकलन तथा प्रभावित आबादी की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों की विशेषज्ञों से जांच कराना आवश्यक है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, जांच की प्रक्रिया विश्वसनीय और पारदर्शी हो। यदि जांच के नमूने लिए जाएं तो उनकी प्रक्रिया, परीक्षण की प्रयोगशाला और रिपोर्ट के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की व्यवस्था हो। इससे न केवल ग्रामीणों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि उद्योगों को भी निष्पक्ष जांच का अवसर मिलेगा।

उद्योग भी जरूरी, पर्यावरण भी

मेघनगर का औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे विवाद को उद्योग बनाम जनता के रूप में देखना उचित नहीं होगा। उद्योगों का संचालन भी जरूरी है और पर्यावरणीय सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी।

जो उद्योग निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई इकाई, नियमों का उल्लंघन करती है और उससे लोगों के स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई में किसी प्रकार की नरमी नहीं होनी चाहिए। विकास और रोजगार की जरूरत अपनी जगह है, लेकिन विकास की कीमत लोगों के स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों से नहीं चुकाई जा सकती।

अब जवाबदेही का सवाल सबसे बड़ा

इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक जवाबदेही है। यदि आज प्रदूषण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जनआक्रोश सामने आया है तो यह भी समीक्षा का विषय होना चाहिए कि अब तक संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी रही।

क्या औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण हो रहा था? क्या प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मानकों की लगातार जांच की गई?

यदि किसी स्तर पर अनियमितता मिली थी तो उस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

और यदि अनियमितता नहीं मिली थी, तो फिर ग्रामीणों की शिकायतों का आधार क्या है?

इन सवालों के जवाब किसी व्यक्ति विशेष को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं।

कलेक्टर की पहल अब परिणाम की कसौटी पर

कलेक्टर की सूझबूझ ने फिलहाल आंदोलन और प्रशासन के बीच संवाद का रास्ता बनाया है। यह निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है। लेकिन प्रशासन की असली परीक्षा अब शुरू होती है।

यदि जनसुनवाई में उठे सवालों पर समयबद्ध कार्रवाई होती है, प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की पहचान होती है, दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होती है और प्रभावित लोगों को राहत मिलती है, तो मेघनगर का यह संकट प्रशासन और जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करने का अवसर बन सकता है।

इसके विपरीत यदि कुछ दिनों बाद मामला फिर फाइलों में दब गया, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई या शिकायतों का समाधान जमीन पर दिखाई नहीं दिया, तो आज बना भरोसा कमजोर भी पड़ सकता है।

इसलिए फिलहाल सबसे उचित निष्कर्ष यही है कि, कलेक्टर ने टकराव को संवाद में बदलने की दिशा में अच्छी पहल की है, लेकिन अब उस संवाद को परिणाम तक पहुंचाना जरूरी है।

मेघनगर की जनता ने अपनी चिंता स्पष्ट रूप से सामने रख दी है। अब उसे आश्वासन से अधिक स्वच्छ पानी, सुरक्षित पर्यावरण, वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध कार्रवाई और स्पष्ट जवाबदेही चाहिए। क्योंकि अंततः किसी भी प्रशासन की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसने आंदोलन को कितनी कुशलता से शांत कराया, बल्कि इससे होती है कि, जिस पीड़ा और शिकायत ने आंदोलन को जन्म दिया था, उसका समाधान कितनी ईमानदारी और स्थायित्व के साथ किया गया। मेघनगर में टकराव टला है, संवाद शुरू हुआ है, अब जनता की नजर इस बात पर है कि यह संवाद समाधान और जवाबदेही तक कब पहुंचता है या नही।

टीईटी की परीक्षा को लेकर शिक्षकों और सरकार में बढ़ता जा रहा गतिरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद।

टीईटी की परीक्षा को लेकर शिक्षकों ओर सरकार में गतिरोध बढ़ता जा रहा है, सरकार लगातार शिक्षकों की मांगों को अनदेखा कर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर टेट की परीक्षा लेने की बात कर रही है। वही शिक्षक इस मुद्दे को लेकर लाम बंद होकर लगातार सरकार से उक्त परीक्षा को लेकर निर्णय बदलने के लिए दबाओ बना रहे है। 31 अगस्त को दिल्ली में प्रदर्शन के बाद एक बार फिर शिक्षक संघ ने टेट परीक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए नारेबाजी की। राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई पेटलावद के आह्वान पर विकासखंड अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं ने मंगलवार को स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रितिका पाटीदार के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के पूर्व सेवारत शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट देने की प्रमुख मांग रखी गई। साथ ही नारे लगाते हुए शिक्षक संगठनों से एक स्वर में कहा कि, किसी भी स्थिति में हम टेट परीक्षा नहीं देंगे न ही परीक्षा आवेदन भरेंगे।

ज्ञापन के समय राज्य कर्मचारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय मखोड़ एवं सचिव तोलसिंह निनामा, प्रताप सिंह सिसौदिया अध्यापक शिक्षक मोर्चा जिला पदाधिकारी के पप्पुसिंह हटीला, आकाश के जिला अध्यक्ष नानूराम गामड़, अजाक्स के जिला अध्यक्ष कैलाश वसुनिया, अध्यापक शिक्षक मोर्चा के रामलाल कटारा, मुकेश पाटीदार, रमेश वाखला, लक्ष्मणसिंह डामर, आशीष व्यास, बीआरसी श्रीमती रेखा गिरी, अर्जुन मालवीय, अंबू डाबी, अनिल निनामा, रमेश सिंगाड़, गोपाल चोयल, श्रीमती रमिला वाखला, जॉन भाबर, अमरसिंह मुणिया ने विशेष रूप से उपस्थित होकर शिक्षक एकता का परिचय दिया। साथ ही शिक्षक संगठन ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि, यदि हमारी मांगे शीघ्र मान ली जाए, नहीं तो आने वाले समय में जिला एवं प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर विशाल रैली एवं ज्ञापन देंगे। जरूरत पड़ी तो मांगे पूरी होने तक भूख हड़ताल भी करेंगे।

सनातन संस्कृति की मूल जड़ हैं : आदिवासी

माही की गूंज, पेटलावद।

समीपस्थ ग्राम कोदली में आदिवासी समाज में जातर ÷नवाई÷ एक पारंपरिक और सांस्कृतिक परंपरा है।÷नवाई भील समाज की वह पारंपरिक परंपरा है, जिसमें नई फसल को सबसे पहले अपने देवी-देवताओं को चढ़ाया जाता है। भील जनजातीय का प्रमुख उत्सव नवाई नई फसलों की उपज का परंपरागत रीति से पूजन कर मनाया जाता है। यह उत्सव नई फसल की अच्छी उपज होने की खुशी में मनाया जाता हैं। सनातन संस्कृति की मूल जड़ है आदिवासी समाज। जिसे गांव का कुलदेवता भी कहा जाता हैं। इस स्थान पर साल भर में सामूहिक सात से आठ कार्यक्रम होते हैं जैसे जातर, सलावनी, उज्जयिनी, नवाई, मांडला, गरबा(मुड़ा) और मान आदि।

झाबुआ जिले में आदिवासी समाज व अपनी सभ्यता

आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को वह आदि अनादि काल से

निर्वहन करते आ रहा है। वह समय-समय पर देवों की पूजा, ईश्वर की पूजा और खत्रीज की पूजा भी करता है।

सबसे पहले गांव की सावन माता, बाबा खेड़ापति देव, खेड़ा ना खात्रिज, लालबाई, फूलबाई, कसुमर बाबा, हनुमान वीर, भोला ईश्वर, माता शीतला, सहित गांव के स्थानीय देवी देवताओं को नया अनाज चढ़ाने के बाद ही नया अनाज खाया जाता है।

आदिवासी समुदाय में खेतों में खड़ी नई फसल जैसे ककड़ी, भूटा, भिंडी, चावल, मूंग, ज्वार आदि पूजा अर्चना के बाद घर के बुजुर्ग द्वारा क्षेत्रों में नई फसल को पहले देवताओं/कुलदेवता को अर्पित किया जाता है।

सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मैंडा का कहना है, यह जातर नवाई सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी बोली, संस्कृति, रीति-रिवाज, पूर्वजों की परंपरा है। नवाई में गांव के तड़वी काना मैंडा, गांव के कोटवार हुरसिंह मैड़ा, बड़वा टीटीया मैंड़ा, सुरजी, धीरजी, अक्कू, झुना, हिमचंद, दिलीप, अन्य गांव के वरिष्ठ उपस्थित हुए थें।

संत को मिली धमकी, दर्ज करवाया विरोध

माही की गूंज, पेटलावद।

सुप्रसिद्ध कथा वाचक कमल किशोर जी नागर को मिले धमकी भरे पत्र को लेकर उनके अनुयायियों में भारी आक्रोश है। बुधवार को उनके अनुयायियों द्वारा नगर के शंकर मंदिर से लेकर पुलिस थाना पेटलावद तक पैदल रैली निकाल कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर ,अज्ञात व्यक्ति जिसके द्वारा उक्त धमकी भरा पत्र दिया उसकी तलाश कर कार्यवाही करने ओर नागर जी की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मांग की गई। ज्ञात है कि चार सितम्बर को मछलियां के भूरा डाबरा स्थित गौशाला पर दर्शन करने वालो लोगो ने से किसी अनजान व्यक्ति ने संत कमल किशोर जी नागर को शाल श्री फल के साथ एक धमकी भरा पत्र दिया गया जिसमें नागर जी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई । पत्र में आदिवासी क्षेत्र में धार्मिक आयोजन करने ,गोशाला के संचालन जैसी गतिविधिया करने पर नाराजगी दिखा कर ,कथा के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। इस पत्र के सामने आने के बाद से ही संत कमल किशोरजी के अनुयायियों में भारी रोष देखा जा रहा है ओर पूरे प्रदेश भर में इस को लेकर ज्ञापन देकर धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने एक महाराज जी को कड़ी सुरक्षा देने की मांग की जा रही है।

तहसीलदार व थाना प्रभारी पेटलावद को ज्ञापन सौंपते नागर जी के अनुयायि।

मातम : सड़क किनारे खड़े युवक पर चढ़ा दी बाइक, युवक की मौत

माही की गूंज, बामनिया।

एक ओर युवक अंध गति से चलाए जा रहे दुपहिया वाहन की चपेट में आकर मौत की निंद सो गया। मंगलवार की रात लगभग 8 बजे बामनिया के रतलाम रोड स्थित चित्तौड़ीरुड़ी निवासी लाला शंभू डामर ओर उसके परिवार के लोग खाना खाकर घर के बाहर सड़क किनारे खड़े थे कि, अंध गति से आए दुपहिया वाहन चालक ने गाड़ी सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें लालू पिता शंभू डामर को गंभीर चोट लगी साथ ही लालू के साथ खड़े उसके तीन छोटे बच्चे ओर उसकी काकी को भी गम्भीर चोट लगी। सूचना के बाद बामनिया पुलिस मौके पर पहुंची ओर एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जहा गंभीर रूप से घायल लालू डामर को मृत घोषित कर दिया गया लालू मात्र 34 वर्ष का था ओर पैशे से ड्राइवर था। पूरे परिवार में तीन बच्चे ओर पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी लालू पर ही थी। लालू की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया। बाकी घायलों का इलाज बामनिया सरकारी ओर पेटलावद सिविल अस्पताल में चल रहा है। हादसे में दुपहिया वाहन सवार को भी चोट आई जिसका इलाज सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में चल रहा है।

मृतक लालू डामर।

एमपीआरडीसी और रोड ठेकेदार की लापरवाही उजागर

ठेकेदार ने काम शुरू कर इस तरह से सड़क पर स्क्रेच डाल कर अधूरा छोड़ा निर्माण।

यहां रतलाम-झाबुआ रोड निर्माण में लगी कम्पनी ओर एमपीआरडीसी की भारी लापरवाही सामने आई है। रोड के ठेकेदार ने रोड निर्माण करने के लिए पुराने रोड को उखाड़ने के लिए अपने वाहन चलाए लेकिन ठेकेदार ने रोड निर्माण बामनिया रेलवे फाटक से लेकर लाड़की नदी तक रोड निर्माण छोड़ कर आगे से कार्य शुरू कर दिया। रोड पर स्क्रेच होने से दुपहिया वाहनों को चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ओर वाहन गिरने की स्थिति में आकर कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते है। ये स्थिति रेलवे फाटक से बस स्टेशन ओर रतलाम रोड स्थित तालाब से लेकर चित्तौड़ीरुडीं तक बनी हुई है। जिस पर सड़क निर्माण एजेंसी ओर एमपीआरडीसी विभाग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तेज गति से चलते वाले वाहन खास कर छोटे वाहन रोड पर बनाए गए स्क्रेच की वजह से सड़क से उतर कर दुर्घटना का शिकार हो रहे है।

संपादकीय

मनमानी कार्रवाई की जवाबदेही तय हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करने के मामले जो टिप्पणियां की हैं, वो देश में राज्य सरकारों के लिये एक गंभीर चेतावनी समझी जानी चाहिए। अदालत ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इस मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए अफसरों के रवैये को तानाशाही वाला बताया है। कोर्ट ने बेहद सख्त भाषा का प्रयोग करते हुए राज्य को ऐसी जगह बताया जहां सरकार का निरंकुश नियंत्रण कानून-व्यवस्था के मामले में हो। स्पष्ट शब्दों में अदालत ने इस घटनाक्रम को मनमाने ढंग से आजादी छीनने वाला बताया। निश्चित रूप से, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार छात्रा की हिरासत को रद्द करने का कोर्ट का फैसला कई गंभीर प्रश्नों को भी जन्म देता है। जो यह भी दर्शाता है कि अधिकारियों द्वारा असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से एक सामान्य मामले में किया जा रहा है। निस्संदेह, इसमें दो राय नहीं कि एहतियाती तौर पर हिरासत में लेना एक असाधारण उपाय है। लेकिन इस गिरफ्तारी को तभी सही ठहराया जा सकता है जब इसे सिद्ध करने के लिये पुख्ता सबूत हों। यानी कि कोई व्यक्ति वास्तव में देश की सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हो। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सामान्य आपराधिक कानून का आसान विकल्प या असहमति की आवाज को दबाने का जरिया नहीं बन सकता है। बताया जाता है कि इस प्रकरण में, खबरों के अनुसार अदालत को कोई ऐसा ठोस सबूत पुलिस उपलब्ध नहीं करा सकी, जिससे यह साबित होता हो कि छात्रा का हिंसा भड़काने में कोई सीधा संबंध रहा हो। उल्लेखनीय है कि मामले में लिप्त अधिकारी कोई ऐसा ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, मसलन व्हाट्स ऐप संदेश या वीडियो उपलब्ध नहीं करा सके, जो यह साबित करता कि छात्रा ने लोगों को दंगे या तोड़-फोड़ के लिये उकसाया था। जिसके बाद ही अदालत ने अभियुक्त की हिरासत रद्द करने के आदेश दिए।

देश का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास इस बात का गवाह है कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना एक जायज अधिकार रहा है। एक स्वतंत्र देश में तो यह अधिकार और सबल हो जाता है। निस्संदेह, किसी संवैधानिक लोकतंत्र में विरोध व प्रदर्शन में शामिल होने और हिंसा भड़काने के बीच फर्क बहुत अहम है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणियां हैं। दरअसल, अदालत ने गिरफ्तारी के समय और आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने के दौरान सामने आई विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को घटना के बाद रची गई कार्रवाई जैसा बताया है। इस घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश है कि घटनाक्रम के लिये जिम्मेदार अधिकारियों से पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए। इतना ही नहीं अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में इस बाबत टिप्पणी दर्ज की जाने का निर्देश दिया गया है। अदालत की सोच रही है कि जब कोई भी अधिकारी सरकारी ताकत का गलत ढंग से इस्तेमाल करता है, तो जवाबदेही सिर्फ सरकारी खजाने तक ही सीमित नहीं रह सकती है। जिसका निहितार्थ यह भी है कि सरकारी कर्मचारी जबर्दस्ती प्रयोग की जाने वाली ताकत के मालिक नहीं हैं, वरन सही मायने में वे उसके संरक्षक होते हैं। वास्तव में उनकी निष्ठा सत्ता के बजाय संविधान और कानून के प्रति ईमानदारी से होनी ही चाहिए। कहने का अभिप्राय यह भी कि लोकतंत्र शोर-शराबे वाले विरोध को तो झेल सकता है, लेकिन ऐसी नौकरशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जो असहमति को व्यवस्था के लिये खतरा समझती है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में अदालत द्वारा की गई सख्त टिप्पणियां देश की राज्यों सरकारों के लिये एक नजीर जैसी हैं। खासकर बेलगाम अधिकारियों के लिये सबक है कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिये लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन नहीं किया जा सकता। किसी भी सख्त कानून का इस्तेमाल करने से पहले अधिकारियों को उसकी तार्किकता को जायज ठहराना चाहिए। अधिकारियों के धैर्य, संयम व विवेक से ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

सवालों के जवाब देकर इस पीढ़ी की पीड़ा करें दूर

विश्वनाथ सचदेव

लगभग तेरह साल पुरानी बात है। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री-पद के उम्मीदवार थे। अपनी योग्यता-क्षमता को दिखाने के लिए उनके पास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया गया काम था। उसी दौरान उन्होंने राजधानी दिल्ली के एक कॉलेज में एक भाषण दिया था। उस भाषण में वह सब था, जो एक उम्मीदवार मतदाता को रिझाने के लिए कह सकता है। सपना दिखाया गया था, वादे किए गए थे। उस भाषण का एक जुमला बहुत चर्चित हुआ था तब–आधे भरे और आधे खाली गिलास वाला मुहावरा। आशावाद और निराशावाद का अंतर समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है और कहा जाता है कि वह आशावादी है, जो गिलास को आधा भरा हुआ बताता है और जो कहता है कि गिलास आधा खाली है, वह निराशावादी है। तब नरेंद्र मोदी ने इस मुहावरे में एक बात और जोड़ी थी, जिसने इस घिसी-पिटी बात को 'ताज़गी' दे दी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'मुझे वह गिलास पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है–आधा पानी से, और आधा हवा से।'

तेरह साल बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के उसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को, और इसके बहाने देश को, संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अवसर कॉलेज के शताब्दी समारोह का था और जो विद्यार्थी उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, वे तब शायद किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। जिन्होंने तेरह साल पहले वाला 'पूरे भरे गिलास' वाला भाषण सुना था, उन्हें वह याद भी था और मेरी तरह शायद वे यह उम्मीद भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे भरे गिलास वाली अपनी बात दोहराएंगे। और प्रधानमंत्री ने भी अपनी कही उस बात को दोहराना ज़रूरी समझा। सामने बैठे विद्यार्थियों के लिए यह बात नई थी। उन्हें भी प्रधानमंत्री का आशावाद अच्छा लगा। तब भावी प्रधानमंत्री ने सपने दिखाए थे, अब वर्तमान प्रधानमंत्री 'अपना रिपोर्ट कार्ड' लेकर उपस्थित थे। पिछले तेरह साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शायद स्वाभाविक था। खूब गिनाईं, और तालियां भी बजीं।

प्रधानमंत्री यह जानते थे कि कॉलेज में पढ़ने वाली जिस पीढ़ी को वे संबोधित कर रहे हैं, वह 'जेन ज़ी' नए मुहावरों को समझती है। देश के युवकों की एक अपनी भाषा है, अपना मुहावरा है उनका। प्रधानमंत्री ने कोशिश की उनसे उनकी भाषा में बात करने की। यह पीढ़ी सपने देखने के बजाय ठोस उपलब्धियों की जानकारी चाहती है। उपलब्धियां गिनाईं उन्होंने। पर यह 'जेन ज़ी' सवाल उठाने वाली है। उपलब्धियों को स्वीकारा जाना चाहिए, पर ऐसे मौके आत्मान्वेषण के भी होते हैं। यह अवसर एक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थान की शताब्दी का था। विद्यार्थी उस शिक्षा-स्थिति के बारे में भी सुनना चाहते थे, जो आज के भारत की चिंता का विषय होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले लगभग अस्सी साल में देश में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा-संस्थान खुले हैं। एक लंबी-चौड़ी सूची है हमारे पास नए-नए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की। लेकिन यह सवाल भी उठता रहा है कि हमारे शिक्षा-संस्थानों को वैश्विक स्वीकार्यता क्यों नहीं मिल पाई। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर शिक्षा के उच्चतम पायदान पर दी जा रही शिक्षा आज सवालों के घेरे में क्यों है? गुणवत्ता और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर बनी चुनौतियों को हम कब देखेंगे–स्वीकारेंगे?

लगभग 17 साल पहले हमने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकार को स्वीकारा था। सर्वशिक्षा अभियान जैसी पहल से स्थिति में कुछ सुधार आया है। पर प्राथमिक शिक्षा में जितना और जैसा सुधार अपेक्षित था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आए दिन सरकारी स्कूलों के बंद होने और निजी स्कूलों के खुलने के समाचार मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति को लेकर पिछले कुछ दिनों में देश में ढेरों सवाल उठे हैं। एक-एक कमरे में चार-चार कक्षाएं एक साथ लग रही हैं। स्कूलों में टाट-पट्टी और शौचालय जैसी ज़रूरी सुविधाओं का भी अभाव है। 'असर' जैसी संस्थाएं बार-बार इस स्थिति को उजागर कर रही हैं कि पांचवीं में पढ़ने वाला बच्चा तीसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा।

जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, उसकी स्थिति भी कुल मिलाकर निराशाजनक ही है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों की पढ़ाई भी उस स्तर की नहीं है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी रोज़गार की अपेक्षाओं की शर्तों पर खरा उतर सके। उच्च शिक्षा के लिए हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाने को प्राथमिकता क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में 'स्पेस सेंटर' बनाने का सपना तो दिखा रहे हैं, पर धरती पर दुर्दशा की हकीकत की गंभीरता को कब समझा जाएगा?

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अपने चर्चित भाषण में प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास अवश्य किया है, पर पूरे भाषण पर चुनावी-साया दिखाई दे रहा है। यह अवसर एक प्रसिद्ध कॉलेज की शताब्दी का था और संयोग से उस दिन शिक्षक-दिवस भी था। यही नहीं, कुछ ही अरसा पहले देश ने 'जेन ज़ी' का असंतोष देखा था और इसी बीच ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की दुर्दशा का मसला भी उभर कर सामने आया है। ऐसे में यह अपेक्षा तो होनी ही चाहिए थी कि प्रधानमंत्री देश में शिक्षा की स्थिति और समस्या पर कुछ कहेंगे। पर इस संदर्भ में कुछ विशेष नहीं कहा उन्होंने। देश की जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना भी ज़रूरी होता है, पर यह कतई ज़रूरी नहीं है कि हमारे राजनेता चुनावी माहौल से उबर ही न सकें। उबरना चाहिए उन्हें। भाषणों में जुमले और मुहावरे अच्छे लगते हैं, पर हमेशा नहीं। शिक्षा-जगत से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने हवा से भरे हुए गिलास और 'दिमाग़ी नक्सल' वाली अपनी बातों को दोहराना ज़रूरी समझा, यह उनका विशेषाधिकार है। युवा पीढ़ी से जुड़ने की उनकी अपनी कोशिश में भी कुछ ग़लत नहीं है, बल्कि ज़रूरी है इस पीढ़ी से जुड़ना, उसकी आकांक्षाओं और चिंताओं को समझना। पर 'नाराज़ फूफा' जैसे जुमले ऐसी कोशिशों को हल्का ही बनाते हैं। हमारे समय और समाज की आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को समझने की ईमानदार कोशिश हो। राजनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर उठकर इस पीढ़ी को समझना होगा। उसकी पीड़ा और उसकी नाराज़गी को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वह निराश है तो उसकी निराशा को समझने की कोशिश होनी चाहिए; वह सवाल उठा रही है तो उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए। बीबीसी ने श्रीराम कॉलेज के कार्यक्रम के बाद कुछ युवाओं से बातचीत की थी। उनमें एक युवक वह भी था, जिसे इसलिए कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वह काली कमीज़ पहने हुए था! उसने बीबीसी के संवाददाता को बताया कि शायद आयोजकों को लगा था कि काली कमीज़ खतरे की घंटी है। मान लेना चाहिए कि उस युवक का कोई ग़लत इरादा नहीं था। उसका काली कमीज़ पहनकर आना एक संयोग हो सकता है। पर यह तय है कि देश की जेन-ज़ी अथवा जेन-अल्फा के पास कुछ सवाल हैं, जो उसे परेशान करते हैं। हमारे नेतृत्व को उनकी परेशानी को समझना होगा। तभी गिलास सही अर्थों में भरेगा।

देशज ज्ञान में हैं संकट से बचाव के उपाय

वीरेन्द्र कुमार

हम हिमालय या अन्यत्र भी प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपभोग या अपव्यय कर रहे हैं, उतना प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हो रहा है। जैव विविधता के मामले में उपभोग या पर्यावरणीय आघातों से जो जैविक जातियां-प्रजातियां संकट में पहुंच गई हैं या समाप्त हो गई हैं, उनकी भरपाई मुश्किल है। क्षेत्रीय आधार पर तो कई जड़ी-बूटियां अतिदोहन के बाद स्थापित ही नहीं हो रही हैं। यह ईकोसिस्टम सेवा क्षमताओं व प्रवाहों पर प्रतिकूल असर डालता है। कई रणनीतियों या चल रहे कार्यक्रमों को मौसम में हो रहे बदलाव प्रभावित कर रहे हैं।

किसी आपदा के बाद जब सरकार अध्ययन कराने की बात करती है, तो वह राजनीतिक रूप से उस समस्या को टालने की प्रक्रिया होती है। जैसे तब तक बरसातें रुक जाती हैं या जंगलों में लगी आग मौसमी कारणों से बुझ जाती हैं। सड़कों के एलाइनमेंट के मामले में भी ऐसा होता है। राजनेता उन क्षेत्रों में सड़क ले जाने के लिए वोट बैंक के कारण दबाव डालते रहते हैं, जिन क्षेत्रों में सड़क ले जाने से जलस्रोतों और वनों को हानि पहुंच सकती है या नए भूस्खलन क्षेत्र बन सकते हैं।

नदी से दूर निर्माण करने के सुझाव ही नहीं माने जाते हैं। इसके लिए तो राजनीतिज्ञ इस हद तक जा सकते हैं कि वे उन सभी दलीलों को जुटा देते हैं, जिनसे बुग्यालों को बुग्याल मानने से ही इनकार कर दिया जाए। नदियों की चौड़ाई पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। बांध जलाशय बन गए तो उनमें मनमाने स्तर तक पानी भरवाने में गुरेज नहीं करते या उस तथ्य की अनदेखी कर देते हैं। इस समय दस राष्ट्रों और लगभग 1.90 अरब लोगों को हिमालय से सेवाएं मिलती हैं। स्थानीय लोगों के ईकोसिस्टम संबंधी ज्ञान का लाभ नहीं लिया जा रहा है। यदि स्थानीय समुदाय को काम दिया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो तो ईकोसिस्टम के पुनर्वास की कीमत कम हो सकती है। नई टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसान कम किए जा सकते हैं और आर्थिकी व पारिस्थितिकी, दोनों को मदद मिल सकती है। पारंपरिक बीज संरक्षण की जानकारी स्थानीय समुदाय आपको दे सकता है। यह पहाड़ी खेती में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता ला सकता है।

आपदाओं के बीच बचे रहने के लिए स्थानीय स्तर के ज्ञान, तकनीकों व अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन और सामयिक उपयोग करने से भविष्य में स्थानीय समुदायों में ज्ञान-कौशल की कुछ विशिष्टताएं भी पनप सकती हैं। बाहरी जगत से संपर्कों के अभाव में दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा व रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें आविष्कार व नवाचार करने ही पड़ते हैं। दुरूह, दुर्गम पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए पीढ़ियों व सदियों से वहां विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहने के लिए स्थानीय स्तर पर काम के तौर-तरीकों, औजारों व ज्ञान को विकसित करना और सहेजना आवश्यक रहा है। ऐसे उदाहरण भी हैं, जब भूकम्पों में भी पीढ़ियों पुराने पहाड़ी मकान या अन्न भंडारण संरचनाएं बची रह जाती हैं। या सूखा, अकाल या अन्य मौसम की मारों के बीच भी स्थानीय लोग पहाड़ों के खेतों व जंगलों में कुछ ऐसा पैदा हुआ पहचान लेते हैं, जिसे स्थानीय निवासी बचे रहने के लिए खा सकते हैं। पहाड़ी आपदाओं से बचाव व राहत में इनसे मदद मिल सकती है।

इस तरह का देशज ज्ञान स्थानीय स्तर पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी झेली जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भों व अनुभवों से ही उपजता है। इसे पिछली पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा देती हैं। अब ऐसे ज्ञान की थाती की निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। पहाड़ों से भारी मात्रा में पलायन भी इसका एक कारण है। बाजारी व्यवस्थाओं से ही जरूरतों के पूरा होने तथा कई प्रकार के प्रतिबंधों के कारण प्राकृतिक क्षेत्रों व संसाधनों से लोगों का दुराव होने के कारण भी पर्वतीय समुदाय के प्रकृति को समझने के अवसरों में कमी आई है। इससे प्रासंगिक आपदा प्रबंधन के देशज ज्ञान की थाती भी सिमटी है।

भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी पहाड़ संवेदनशील संतुलन में हैं। यहां आपदाओं से सहज प्रभावित होने वाली संरचनाएं हैं। भू-उपयोग परिवर्तन भूपारिस्थितिकी, भू-संस्कृति और लोगों की मांगों व पसंद में भी अंतर ला रहा है। स्थानीय लोग जब बाहर की चीजें मांगेंगे तो निर्भरता बढ़ेगी। जब बादल फटता है या भीषण बरसात आती है, तो सड़कों की मोड़दार, तेज ढालों से पानी के बहाव और उसकी शक्ति में अप्रत्याशित तेजी आती है। इससे नीचे के मकानों, खेतों, मैदानों और सूखे नालों में बजरी, पत्थर व मलबा भारी मात्रा में आकर नुकसान कर देता है। सड़कों को पहाड़ों से काटते वक्त पहाड़ों का स्थिर प्राकृतिक ढलान बिगड़ जाता है। ये अस्थिर ढलान बादल फटने के समय लगातार भूस्खलन वाले क्षेत्र बन जाते हैं।

हिमालयी विकास केवल विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है। यह ज्ञान, अनुभव व पारंपरिकता का भी विषय है। वहां के रहने वाले अपने-अपने स्तर पर जिन तौर-तरीकों से बचे रहना चाहते हैं, उन पर अपना विज्ञान न थोपें। जिन तरीकों से वे सफलता से बचे रह रहे हैं, हिमालय से कम-से-कम संसाधन लेते हुए उनके पीछे के विज्ञान को समझिए। तब उनके लिए मददगार वातावरण बनाएं।

चेक बाउंस विवादो मे तकनीक बने समाधान

डॉ. सुधीर कुमार

देश की अदालतों में करोड़ों लंबित मामलों में से एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 यानी चेक बाउंस के मामलों की है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक, चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इनमें से अधिकांश विवाद वित्तीय लेन-देन से जुड़े असंतोष या छोटी-मोटी चूकों के कारण होते हैं। इसके बावजूद, एक साधारण-सा चेक बाउंस होने पर कानूनी नोटिस भेजने से लेकर अदालत में समन जारी होने, गवाही, जिरह और फैसले तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में माना है कि इन मुकदमों का अंतहीन चलना व्यापारिक जगत और न्यायपालिका, दोनों के लिए घातक है।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण और लैंडमार्क फैसले हैं। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले 'इन री–एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेज अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, 1881 (2020)' में बड़ी बेंच ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई थी कि देश की अदालतों में चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं और इनका अंतहीन चलना न्याय व्यवस्था व व्यापारिक माहौल, दोनों के लिए घातक है। इसके साथ ही, 'दशरत रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र' (2014) के ऐतिहासिक मामले में भी न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि पारंपरिक मुकदमेबाजी में वादी और प्रतिवादी, दोनों का धन, समय और मानसिक सुकून नष्ट होता है। न्यायालयों ने कई बार मध्यस्थता और त्वरित न्याय प्रणालियों पर जोर दिया है, क्योंकि जिस मामले को बैंक स्तर पर या चंद दिनों में सुलझाया जा सकता है, उसे वर्षों तक कचहरी के चक्कर कटवाए जाते हैं।

इस स्थिति में हमें लीक से हटकर सोचना होगा और एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल अपनाना होगा, जो पूरी तरह तकनीक पर आधारित हो। यहां एक अनूठा और आधुनिक तरीका काम आ सकता है–'स्मार्ट-ब्रीच ऑटो-रेज़ोल्यूशन पोर्टल'। कल्पना कीजिए कि जैसे ही किसी व्यक्ति का चेक बैंक में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस होता है, पारंपरिक कागजी प्रक्रिया शुरू होने के बजाय एक स्वचालित डिजिटल ट्रिगर सक्रिय हो जाए।

इस नए मॉडल के तहत, बैंक स्तर पर ही एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर काम करे, जो तुरंत संबंधित व्यक्ति के खाते से एक निश्चित डिजिटल पेनल्टी और मूल राशि का आंशिक या पूर्ण ट्रांसफर सुनिश्चित करे; बशर्ते दोनों पक्षों के बीच पहले से डिजिटल एग्रीमेंट हो। यदि राशि को लेकर विवाद है, तो मामला सीधे कोर्ट जाने के बजाय ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म पर डायवर्ट हो जाए।

ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा वर्चुअल कोर्ट रूम या मध्यस्थता मंच है, जहां कोई वकील, कोई तारीख और कोई कागजी फाइल नहीं होती। दोनों पक्ष घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं। एक प्रशिक्षित एआई-असिस्टेड मीडिएटर या डिजिटल एल्गोरिद्म दोनों पक्षों के डिजिटल रिकॉर्ड को खंगालकर 7 से 15 दिनों के भीतर एक बाध्यकारी समझौता प्रस्ताव तैयार कर देता है। यदि कोई पक्ष इसका उल्लंघन करता है, तो उसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल स्कोर स्वतः डाउन हो जाता है और उसके अन्य बैंक खातों पर स्वचालित डिजिटल होल्ड लग जाता है। यह तरीका न केवल अदालतों का बोझ कम करेगा, बल्कि आम आदमी को मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाएगा।

डिजिटल न्याय प्रणाली की सफलता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समझ, इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी जैसी व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। ग्राम स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से डिजिटल हेल्प डेस्क बनाए जाने चाहिए, ताकि मुफ्त या कम शुल्क में तकनीकी सहायता मिल सके। जब तक डिजिटल साक्षरता और समावेशी मॉडल विकसित नहीं होंगे, तब तक न्याय का स्थानीयकरण अधूरा रहेगा।

कानूनी ढांचे में दूरगामी बदलाव करते हुए सबसे पहले चेक बाउंस जैसे मामलों में प्री-लिटिगेशन मेडिएशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे बैंक खाते से संदेश आते ही 15 दिनों की ऑनलाइन बातचीत के जरिए आधे से अधिक मामले अदालत पहुंचने से पहले ही सुलझ सकें। इसके साथ ही, कंपाउंडिंग यानी समझौते के नियमों का स्वतः क्रियान्वयन लागू होना चाहिए, ताकि आरोपी द्वारा डिजिटल माध्यम से मूल राशि व हर्जाना जमा करते ही, बिना अदालती चक्कर और जज की अनुमति के, मामला स्वतः समाप्त होकर सिस्टम से केस क्लोजर रिपोर्ट जारी हो सके।

चेक बाउंस के मामलों में लोग जेल जाने के डर से भागते फिरते हैं या कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर वर्षों तक तारीखें लेते रहते हैं। हमें जेल भेजने की पुरानी ब्रिटिशकालीन मानसिकता से बाहर निकलकर कड़े वित्तीय दंड और दीर्घकालिक सिबिल पाबंदियों को सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। जानबूझकर चेक बाउंस करने वालों पर चेक राशि का 3 से 5 गुना भारी जुर्माना लगाया जाए, जो सीधे पीड़ित को मिले, और उनका सिबिल स्कोर इतना गिरा दिया जाए कि वे अगले 5 वर्षों तक नया लोन या क्रेडिट कार्ड न पा सकें। जब व्यक्ति के वित्तीय जीवन पर सीधा प्रहार होगा, तो वह अदालती चक्कर काटने के बजाय समय पर भुगतान करना खुद-ब-खुद सीख जाएगा।

जब तक हम प्री-लिटिगेशन मेडिएशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और डिजिटल ऑटोमेशन को न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक तारीखों के इस जंजाल से राहत नहीं मिल सकती।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर मध्यप्रदेश में फिर पत्थरबाजी

माही की गूंज, रतलाम।

दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे पर पत्थरबाजी का खतरा फिर सिर उठाने लगा है। सोमवार रात झाबुआ से रतलाम लौट रहे रोटरी इंटरनेशनल मंडल डिस्ट्रिक्ट 3040 के गवर्नर संस्कार कोठारी की कार पर बदमाशों ने माही नदी की पुलिया के पास बड़ा पत्थर फेंका। पत्थर सामने के कांच पर ड्राइवर की दूसरी ओर लगा और कांच चकनाचूर होकर कोठारी के ऊपर तथा कार के भीतर बिखर गया।

गनीमत रही कि चालक ने कार रोकी नहीं, वरना तेज रफ्तार एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हो सकता था। इसी दौरान तीन अन्य कारों पर भी पत्थर फेंके गए। घटना थांदला से करीब 15 किलोमीटर रतलाम की ओर, माही नदी की पुलिया के पास रेस्ट एरिया के नजदीक हुई।

कोठारी के अलावा तीन अन्य कारों पर भी बदमाशों ने पत्थर बरसाए। सभी ने टोल बूथ पर आकर विरोध दर्ज कराया। पुलिस को नाइट विजन ड्रोन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कुछ माह से ड्रोन से निगरानी बंद कर दी गई है।

कोठारी सोमवार शाम करीब 5 बजे रोटरी के काम से फोर्ड एमजे कार (एमपी 09 डब्ल्यूएच 5373) से झाबुआ गए थे। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच रतलाम लौटते समय अचानक जोरदार आवाज हुई और पत्थर कांच पर आकर लगा। कार ड्राइवर विजय सिंह राठौर ने कार रोकने के बजाय गति बनाए रखते हुए सीधे धामनोद टोल पहुंचाया।

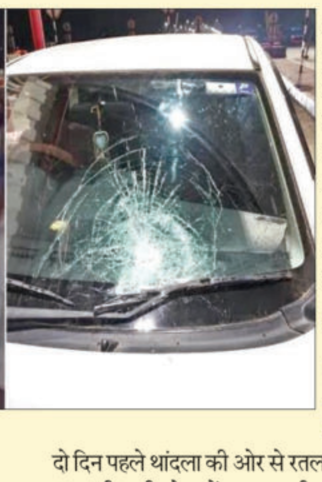

रास्ते में 1033 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी गई, जहां से 112 पर सूचना देने को कहा गया। इसके बाद 112 पर भी सूचना दी। धामनोद टोल पहुंचने पर कोठारी ने एटलेन के अधिकारियों को घटना बताई। पुलिस और एक्सप्रेस-वे अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने शिकायत दर्ज की, जबकि पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र थाने में लिखित आवेदन देने को कहा। रात अधिक होने के कारण कोठारी मंगलवार सुबह औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे और शिकायत दी।

लगातार हो रही वारदात

दो दिन पहले थांदला की ओर से रतलाम आ रही एक कार पर भी इसी क्षेत्र में पत्थरबाजी हुई थी। इसके अलावा रतलाम से थांदला की ओर जा रही दो-तीन कारों पर पत्थर फेंके गए, जिनके चालक थांदला में उतर गए। लगातार हो रही घटनाओं से वाहन चालकों में भय है। बदमाश झाबुआ-रतलाम सीमा पर पहाड़ियों से नीचे सड़क पर पत्थर फेंक रहे हैं और नीचे माही नदी बहती है। रतलाम पुलिस झाबुआ पुलिस से भी संपर्क कर रही है।

एक्सप्रेस-वे सुविधा के लिए या खतरे के लिए

कोठारी ने रात में टोल पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि पत्थर लगने के बाद कार नहीं रोकने से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक्सप्रेस-वे लोगों की सुविधा और सुरक्षित सफर के लिए बनाया गया है या वाहन चालकों को नुकसान और लूटपाट के खतरे के लिए। घटना के बाद अब भी मन में डर बना हुआ है। एटलेन पर पहले भी पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

इन्हें रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी भी शुरू की गई थी, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं थम नहीं रही हैं। रेस्ट एरिया और माही नदी की पुलिया के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी निगरानी और नियमित पेट्रोलिंग की जरूरत है।वाहन चालक भारी टोल चुकाकर सुरक्षित सफर की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं सुरक्षा के दावों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। 25 किमी के अंतराल पर मेंटनेंस कंपनी की गश्त रहती है, लेकिन बावजूद इसके पत्थरबाजी रूक नहीं रही है।

सावधान : ये रतलाम कलेक्टर का फोटो जरुर है, मैसेज नहीं, प्रशासन में हडक़ंप

माही की गूंज, रतलाम।

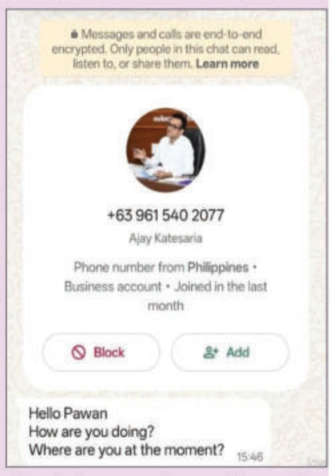

एक कथित नंबर के वाट्सएप डीपी पर रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया की फोटो लगाकर जिले के कई विभागों के अफसरों को हाय-हेलो के मैसेज भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस नंबर से महिला एवं बाल विकास विभाग के कई अफसरों को मैसेज भेजे गए हैं। इसकी जानकारी जिला प्रशासन के संज्ञान में आई तो हडक़ंपमच गया। तुरत-फुरत में जिला प्रशासन की तरफ से जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से एक संदेश प्रसारित करवाया गया कि इस कथित नंबर +639615402077 से आने वाले मैसेज पर कोई पैसा नहीं डाले और न ही संपर्क करें। जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया कि यह नंबर कलेक्टर कटेसरिया का अधिकृत नंबर नहीं है। मोबाइल पर आने वाला +63 फिलिपिंस का है जबकि भारत का कोड +91 है।

कलेक्टर कटेसरिया ने नागरिकों एवं जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों से अपील की है कि उक्त नंबर अथवा किसी अन्य अनधिकृत नंबर से कलेक्टर के नाम, फोटो अथवा पद का उपयोग करते हुए कोई संदेश प्राप्त होता है, तो उस पर विश्वास नहीं करें। ऐसे संदेशों के माध्यम से पैसों की मांग अथवा अन्य प्रकार की धोखाधड़ी किए जाने की आशंका हो सकती है। कलेक्टर कटेसरिया ने स्पष्ट किया है कि +639615402077 नंबर उनका अधिकृत नंबर नहीं है। इस नंबर से प्राप्त किसी भी संदेश, कॉल अथवा पैसों की मांग पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दें और न ही किसी बैंक खाते, यूपीआई अथवा अन्य माध्यम से राशि का भुगतान करें।

कलेक्टर ने कहा कि साइबर अपराधी अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम और फोटो का उपयोग कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। वे ऐसा करके संबंधित पर दबाव बनाकर रुपयों की अनैतिक मांग भी कर सकते हैं। इसलिए किसी भी अनजान नंबर से प्राप्त संदेश की सत्यता की पुष्टि किए बिना कोई व्यक्तिगत जानकारी, बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड अथवा राशि साझा नहीं करें।

सबको जानता होगा यह व्यक्ति

जिस नंबर के वाट्सएप डीपी पर कलेक्टर कटेसरिया की फोटो लगाई गई वह फोटो महज एक दिन पूर्व की है। यह फोटो जनसंपर्क कार्यालय से जारी की गई थी। साथ ही जिन अफसरों को ये मैसेज भेजे गए वह उन्हें निश्चित रूप से जानता होगा या उनके नंबर उस व्यक्ति के पास होंगे। ज्यादातर मैसेज महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों के मौबाइल पर भेजे गए हैं।

चादर पर लिटाकर बीमार वृद्धा को जनसुनवाई में लेकर पहुंचे स्वजन

माही की गूंज, रतलाम।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब परिजन 68 वर्षीय बीमार वृद्धा को चादर पर लिटाकर उठाते हुए जनसुनवाई कक्ष में ले आए। वृद्धा की हालत ऐसी थी कि वह न तो उठ पा रही थीं और न ही बैठ सकती थीं।

उन्हें इस तरह लाया गया देखकर एसपी अमित कुमार ने नाराजगी जताते हुए परिजनों से कहा कि आवेदन लेकर वे स्वयं आ सकते थे। यदि उन्हें सूचना दी जाती तो वे खुद नीचे आकर शिकायत सुन लेते। एसपी ने स्वजनों से कहा कि इस अवस्था में वृद्धा को इस तरह तकलीफ देकर लाना उचित नहीं है और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए।

इस पर स्वजनों ने बताया कि वृद्धा स्वयं एसपी से मिलकर अपनी आपबीती और शिकायत बताने की जिद पर अड़ी थीं। इसी वजह से उन्हें इस हालत में लेकर आना पड़ा। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो ने वृद्धा और उनके परिजनों की शिकायत सुनी तथा संबंधित थाने को मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

मकान की रजिस्ट्री कराने का आरोप

शिकायती पत्र के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के अलकापुरी निवासी पुष्पा देवी, पति स्व. जगदीशचंद्र जी, उम्र 68 वर्ष ने अन्नूबाई चावडा, है कालुराम, सुमित चावडा एवं यश शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी और छल-कपट के आरोप लगाए हैं। वृद्धा का कहना है कि उनकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने घरेलू काम के लिए अन्नूबाई को रखा था। आरोप है कि उनकी अस्वस्थता का फायदा उठाकर उन्हें धोखे और अंधेरे में रखकर मकान की वसीयत और विक्रय-पत्र अपने नाम करवा लिया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 22 अप्रैल 2026 को जालसाजी कर 8 लाख 90 हजार रुपए का फर्जी प्रतिफल दर्शाते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय में मकान की रजिस्ट्री करा ली गई। इसके साथ ही वृद्धा के बैंक खातों से एफडी और जमा राशि के करीब 17 लाख 64 हजार रुपए तुड़वाकर अथवा ट्रांसफर करवाकर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

भतीजे के साथ मारपीट का भी आरोप

वृद्धा ने शिकायत में बताया कि अगस्त में उनके भतीजे मकान की देखभाल के लिए आए थे। आरोप है कि उस दौरान आरोपितों और करीब 15 से 20 असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने शिकायत सुनने के बाद संबंधित थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक

सीहोर।

पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोरीन गैस जब अचानक हवा में फैल जाए तो क्या होगा? आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और फिर लोगों का अस्पताल की तरफ दौड़ना... मध्य प्रदेश के सीहोर में कुछ ऐसा ही हुआ है।

मामला सीहोर जिले के लसुड़िया खास गांव का है। यहां एक पानी फिल्टर प्लांट है, जहां तालाब के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसी दौरान क्लोरीन गैस के टैंक में लीकेज हो गया।

गैस टैंक से बाहर निकली तो आसपास मौजूद लोगों को इसका असर महसूस होने लगा। कुछ लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी, तो कुछ को सांस लेने में परेशानी हुई। देखते ही देखते इलाके में हड़कंप मच गया।

गैस के संपर्क में आए लोगों को इलाज के लिए सीहोर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्रभावित लोगों का इलाज करना शुरू किया। अस्पताल पहुंचे लोगों की हालत को लेकर चिंता जरूर थी, लेकिन डॉक्टरों ने राहत की खबर दी. जिला अस्पताल के डॉक्टर हरिओम गुप्ता के मुताबिक, गैस से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को गंभीर परेशानी नहीं हुई है और सभी लोग खतरे से बाहर हैं।

पानी साफ करने वाली गैस ने बढ़ाई चिंता

क्लोरीन का इस्तेमाल आमतौर पर पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। लसुड़िया खास के इस फिल्टर प्लांट में भी तालाब के पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग हो रहा था. लेकिन टैंक में लीकेज के बाद यही गैस लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गई।

घटना की सूचना के बाद प्लांट में स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू की गईं। हालांकि, गैस लीक होने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

राहत की बात यही है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जरूर हुई, लेकिन किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। सभी प्रभावित लोग खतरे से बाहर हैं। लोगों का सवाल है कि पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा क्लोरीन गैस का टैंक आखिर लीक कैसे हुआ? और क्या प्लांट में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे?

आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज थाने पहुंचा

माही की गूंज, शाजापुर।

मक्सी थाना क्षेत्र के ग्राम झोंकर में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिला। मामले को लेकर बुधवार को झोंकर के मुस्लिम समाज के बड़ी संख्या में लोग मक्सी थाने पहुंचे और पुलिस को आवेदन देकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई एवं गिरफ्तारी की मांग की।

मुस्लिम समाज द्वारा पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया गया कि झोंकर निवासी नितिन इंद्रिया पाटीदार पिता राजेश इंद्रिया पाटीदार द्वारा गत दिनों आपत्तिजनक एवं गुस्ताखी भरी टिप्पणी की गई। समाजजनों का कहना है कि टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसे लेकर समाज में नाराजगी है और मामले में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

पुलिस से कार्रवाई की मांग

आवेदन में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस से मांग की कि मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाए और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाए। समाजजनों ने पुलिस को मामले से संबंधित जानकारी एवं उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने की भी मांग की।

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मामले को लेकर एसआई मनोहर चौहान ने बताया कि ग्राम झोंकर में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच में तथ्य सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामले के बाद पुलिस ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। समाजजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया सांड

श्योपुर। उक्त मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर का है। यहां एक सांड ने ऐसा कारनामा कर दिया कि गांव वालों से लेकर पुलिस और प्रशासन तक सबकी नजर उसी पर टिक गई। मामला श्योपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर ददूनी गांव का है। गांव में बनी पानी की एक ऊंची टंकी पर एक सांड चढ़ गया।

टंकी की ऊंचाई करीब 60 फीट बताई जा रही है। अब सांड ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसे नीचे उतारना आसान नहीं था। सांड को टंकी पर देखकर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई ऊपर देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये नीचे आएगा कैसे? ग्रामीणों ने सांड को नीचे उतारने की कोशिश भी की। लेकिन मामला आसान नहीं था।

ददूनी पंचायत के सचिव महेश गौड़ के मुताबिक, सांड पर लगातार नजर रखी जा रही थी और प्रशासन व पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी। बताया गया कि सांड ने एक बार नीचे आने की कोशिश भी की थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ खड़ी थी। बस फिर क्या था। सांड नीचे आने के बजाय वापस ऊपर चला गया। यानी नीचे भीड़ थी और ऊपर सांड।

समय गुजरता गया, लेकिन सांड टंकी से नीचे नहीं आया। रविवार की शाम से लेकर मंगलवार तक वह करीब 42 घंटे तक 60 फीट ऊंची टंकी पर फंसा रहा। इस दौरान उसकी निगरानी की जा रही थी। पंचायत की तरफ से उसके खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उसे सुरक्षित नीचे उतारना। क्योंकि इतनी ऊंचाई से जानवर को नीचे लाने में जरा सी चूक भी खतरनाक हो सकती थी। सांड को नीचे उतारने की कई कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। इसके बाद मंगलवार को प्रशासन ने श्योपुर से एक क्रेन मंगवाई। अब मैदान में पुलिस थी, पशुपालन विभाग की टीम थी और प्रशासन भी था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मानपुर थाना प्रभारी सतीश दुबे के मुताबिक, पुलिस टीम ने पशुपालन विभाग के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पशु चिकित्सा अधिकारी सचिन उपाध्याय ने सांड को बेहोशी की दवा दी। इसके बाद क्रेन की मदद से उसे सावधानीपूर्वक नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई।

पर्वाधिराज पर्युषण : शास्त्रों में श्रावकों के चार और साधुओं के लिए पांच कर्तव्य निहित

माही की गूंज, रतलाम।

पर्वाधिराज पर्युषण आत्मा को निर्मल बनाने आए है। पर्युषण के आठों दिन आत्मा के साथ जियो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और माया सभी कषायों से दूर रहकर आत्म साधना करो। आठ दिन अपने मन को मोडना है। यदि इन दिनों में आत्मा की शुद्धि के लिए साधना कर ली, तो सुखी हो जाओगे।

यह विचार प्रवर्तक प्रकाश मुनि निर्भय ने पर्वाधिराज पर्युषण के पहले दिन धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मोहन टाकीज स्थित सौभाग्य प्रकाश दरबार में धर्मसभा को उपप्रर्वतनी, महासती, प्रवचन प्रभाविका सुमनप्रभा एवं महासती चंदनबाला ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश एवं देश विभिन्न स्थानों से गुरुभक्तों ने रतलाम पहुंचकर धर्मलाभ लिया। सेवाभावी दर्शनमुनि, महासती कल्पना मंचासीन रहे। धर्मसभा का संचालन प्रकाश मूणत ने किया।

पर्युषण के दिनों में क्या करें

प्रवर्तक मुनि ने कहा कि पर्युषण के दिनों में शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। शास्त्र अनुसार जो भी नियम बताए गए है, उनका पालन करना चाहिए। शास्त्रों में श्रावकों के लिए चार और साधुओं के लिए पांच कर्तव्य निहित है, जिनका पालन करते हुए साधना करना चाहिए। पर्युषण का अंतिम दिन क्षमा का है। यदि किसी से कोई भूल हो जाए अथवा वर्ष भर में किसी का दिल दुखाया हो, तो इस दिन क्षमा याचना कर लेना चाहिए। इससे मन हल्का हो जाता है और मन हल्का रखने वाला सदैव सुखी रहता है।

तपस्याएं जारी, 41 सूत्रीय संकल्प पत्र

प्रवर्तक मुनि की निश्रा में मंगलवार को महासती चंद्रयशा ने 35 उपवास के प्रत्याख्यान में 34 उपवास की तपस्या पूर्ण की। प्रखर गंग ने 24 उपवास और क्रिजंल मेहता के 23 उपवास के प्रत्याख्यान लिए। अन्य तपस्वियों ने अलग-अलग तपस्या के प्रत्याख्यान लिए। धर्मसभा में 41 सूत्रीय संकल्प पत्र का वितरण किया गया। इसमें श्रावक-श्राविकाओं से रात्रि भोजन त्याग सहित विभिन्न प्रकार के त्याग का संकल्प का आव्हान किया गया है।

सामूहिक अष्टठाई का संकल्प किया

श्वेताम्बर जैन समाज का पर्वाधिराज पर्युषण पर्व मंगलवार से शुरू हो गया। 20 सितंबर तक मंदिरों पर अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। पाश्र्वनाथ मित्र मंडल ट्रस्ट टीआईटी रोड श्रीसंघ जैन धर्मशाला पर प्रथम दिन अष्टान्हिका प्रवचन सुबह 9 बजे से हुए। इस दौरान सामूहिक अष्टठाई का संकल्प किया। 11 सितंबर कल्पसूत्र वाचन सुबह 8.30 बजे से शुरू होगा। 12 सितंबर को जन्मवांचन प्रवचन सुबह 8.30 बजे से होंगे। इस दौरान सपनाजी एवं अष्टमंगल के चढ़ावे सुबह 10.30 बजे से होंगे। 15 सितंबर को संवत्सरी महापर्व मनाया जाएगा। सुबह 8.30 बजे प्रवचन के बाद चैत्य परिपाटी एवं वार्षिक प्रतिक्रमण शाम को होगा। 16 सितंबर को सामूहिक क्षमापना पर्व सुबह 8.30 बजे से मनाया जाएगा। रथयात्रा 20 सितंबर सुबह 8.30 बजे निकाली जाएगी।

पर्युषण पर्व प्रथम दिन प्रभु नमीनाथ के दर्शन-वंदन

कस्तूरबा नगर जिनालय में पर्युषण पर्व की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ हुई। सुबह से ही प्रभु नमीनाथ के दर्शन, वंदन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। सुबह 9 से 11 बजे तक उपाश्रय में साध्वी के प्रवचन हुए। समाजसेवी अमित कोठारी ने बताया कि दोपहर में स्नात्र पूजा रखी गई। शाम 6.45 बजे प्रतिक्रमण हुआ और रात 9 बजे बिबड़ौद नवयुवक मंडल परिवार की ओर से आरती का आयोजन किया। इसके बाद बहु मंडल ने भाव यात्रा रखी। इस अवसर पर न्यास मंडल अध्यक्ष बाबूलाल सियार, राजेंद्र कोठारी, अशोक कोठारी, देवेंद्र पुगलिया, कनकमल जैन, प्रमोद रांका, लोकेश ओस्तवाल आदि बड़ी संख्या में धर्मालु मौजूद रहे। भाव यात्रा के लाभार्थी संजय मांडलेचा परिवार रहा।

कारोबारी तायल बंधुओं के ठिकानों पर ईडी की दबिश

माही की गूंज, सेंधवा।

बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कारोबारी अशोक तायल और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर कार्रवाई की। जांच दल ने जगन्नाथपुरी कॉलोनी स्थित उनके निवास, पुराने एबी रोड स्थित मकान और वरला रोड स्थित राजराजेश्वर जिनिंग कारखाने में जांच की। कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई और दोपहर तक अलग-अलग स्थानों पर जांच जारी रही। पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल ने सेंधवा में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की पुष्टि की है। हालांकि, जांच किस मामले को लेकर की जा रही है और किन दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई राजराजेश्वर वेंचर्स से जुड़े करोड़ों रुपए के ऋण मामले से संबंधित हो सकती है।

बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीमें तायल बंधुओं के अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचीं। टीम ने कई कमरों में दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच की। दोपहर करीब 2 बजे एक दल वरला रोड स्थित राजराजेश्वर वेंचर्स के परिसर से बाहर निकला। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई।

तायल बंधु सेंधवा के प्रमुख कपास व्यापारियों और उद्योगपतियों में शामिल हैं। उनका कपास की जिनिंग फैक्ट्रियों का कारोबार है। बड़वानी जिले के अलावा महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी उनका कारोबार संचालित होता है। सेंधवा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित निमाड़ कृषि पार्क का संचालन भी तायल बंधुओं से जुड़ा बताया जाता है।

करीब आठ महीने पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी तायल बंधुओं से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई नाबार्ड बैंक भोपाल से जुड़े 13 करोड़ रुपए के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई थी। उस समय केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने पुलिस बल के साथ जगन्नाथपुरी कॉलोनी स्थित अशोक तायल के निवास सहित अन्य ठिकानों पर तलाशी ली थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, निमाड़ कृषि पार्क से जुड़े अर्पित राजेंद्र कुमार तायल, निकुंज गिरधारीलाल तायल, अशोक बिहारीलाल तायल और अंकित गिरधारीलाल तायल सहित कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और दस्तावेजों में जालसाजी के आरोप लगाए गए थे।

जांच एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2019 में आरोपियों ने नाबार्ड की खाद्य प्रसंस्करण निधि योजना के तहत सेंधवा के पास जामली गांव में कृषि प्रसंस्करण समूह

परियोजना के लिए 13 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। परियोजना की कुल लागत 31 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई थी। इसमें केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से 10 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत होने की बात भी सामने आई थी।

जांच में आरोप लगाया गया कि परियोजना पर राशि खर्च करने के बजाय कथित तौर पर फर्जी समझौतों के माध्यम से ऋण की रकम अन्य कंपनियों और खातों में स्थानांतरित की गई। परियोजना की समय-सीमा बढ़वाकर बैंक अधिकारियों को गुमराह करने के भी आरोप लगाए गए। सितंबर 2024 में ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किए जाने के बाद लेखा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए पत्र भेजा गया था। अब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

दो सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के कसरावद थाना क्षेत्र में मंगलवार रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की जान चली गई। छोटी कसरावद में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जबकि सादड़बन (देवजीरी) में एक किशोर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया।

जानकारी के अनुसार, अभिषेक (22) और गौतम (22) बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

इसी रात सादड़बन (देवजीरी) में 15 वर्षीय देवकरण अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

कसरावद थाना पुलिस ने दोनों घटनाओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहनों और उनके चालकों की तलाश की जा रही है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। एक ही रात में तीन युवकों की मौत से क्षेत्र के लोगों में शोक व्याप्त है।

100 रुपए के विवाद में हत्या, दोषियों को 10 साल की सजा

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के पाटी में 100 रुपए उधार देने के बाद वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एल.डी. सोलंकी की अदालत ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

मामला 29 मार्च 2026 का है। फरियादी किताराम (20) ने पाटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई फुलसिंग (35), निवासी जमरा फलिया, पाटी-गंधावल मार्ग पर टंटेश्वर महादेव मंदिर के सामने स्थित छब्बानिया के खेत में गया था। वहां मनीष बारेला, निवासी पटेल फलिया पाटी, ने फुलसिंग से 100 रुपए उधार मांगे। फुलसिंग ने उसे रुपए दे दिए। कुछ समय बाद जब फुलसिंग ने अपने रुपए वापस मांगे तो मनीष ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा।

विवाद बढ़ने पर मनीष ने अपने साथी रणछोड़ बारेला और वीरेंद्र बारेला के साथ मिलकर फुलसिंग की लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसके सीने, मुंह, पेट और गुप्तांगों पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। मारपीट में गंभीर रूप से घायल फुलसिंग की मौत हो गई।

किताराम की शिकायत पर पाटी पुलिस ने मनीष बारेला, रणछोड़ बारेला और वीरेंद्र बारेला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के दौरान घटना से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य, हथियार और गवाहों के बयान जुटाए गए। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मनीष पिता काशीराम बारेला (24), रणछोड़ पिता अम्बाराम बारेला (23) और वीरेंद्र पिता सखाराम बारेला (20), सभी निवासी पटेल फलिया, ग्राम पाटी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने 8 सितंबर 2026 को तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले की विवेचना पाटी थाना प्रभारी रामदास यादव ने की। न्यायालय में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव ने पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी, मानदेय बढाने की मांग

माही की गूंज, खंडवा।

मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर डॉक्टरों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें शासन तक पहुंचाने का आग्रह किया।

इंटर्न डॉक्टर वर्तमान में मिल रहे 14 हजार 337 रुपए प्रतिमाह मानदेय को बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान वे मरीजों की देखभाल के साथ चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें उचित मानदेय दिया जाना चाहिए। डॉक्टरों ने मानदेय बढ़ाने के संबंध में जल्द लिखित आश्वासन देने की मांग भी रखी है।

इससे पहले मंगलवार को इंटर्न डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सुबह करीब 11 बजे धरना शुरू किया था। करीब एक घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद डॉक्टर दोपहर करीब 12 बजे मुख्य मार्ग पर पहुंच गए थे। यहां उन्होंने करीब दो घंटे तक रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। इसके बाद वे वापस मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान डॉक्टरों ने भोपाल में आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन में भी आवाज उठाई।

बुधवार को कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मानदेय बढ़ाने के साथ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया गया। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पानी की बौछार और लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच और कार्रवाई की मांग की।

इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। डॉक्टरों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि जब तक मानदेय बढ़ाने को लेकर ठोस निर्णय और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बुधवार को बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टर बाइक रैली में शामिल हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी है।

नई तकनीक अपनाकर खेती को बनाएं लाभकारी - कलेक्टर

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर जयति सिंह ने किसानों से खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई तकनीक अपनाने की अपील की। उन्होंने यह बात राजपुर विकासखंड के नंदगांव में बुधवार रात आयोजित 20वीं रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद के दौरान कही। कलेक्टर ने कहा कि पारंपरिक खेती में उत्पादन और आमदनी सीमित रहती है, जबकि नई तकनीक और आधुनिक तरीकों को अपनाकर खेती को लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी क्रम में किसानों से सीधे संवाद और उनकी समस्याओं को समझने के लिए गांवों में रात्रि चौपाल आयोजित की जा रही हैं। नंदगांव में कपास की खेती का बड़ा रकबा होने के कारण कलेक्टर ने अधिक घनत्व वाली कपास खेती पद्धति और लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

चौपाल के दौरान एक महिला किसान ने चिया बीज की सफल खेती का अनुभव साझा किया। कलेक्टर ने अन्य किसानों और महिला समूहों को कम लागत में बेहतर आमदनी देने वाली फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मशरूम, सफेद मूसली और अश्वगंधा जैसी फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी। प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन, प्रमाणन और मिलने वाली आर्थिक सहायता की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई।

पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों ने युवाओं को आचार्य विद्यासागर योजना सहित मुर्गीपालन, बकरीपालन और पशुपालन से जुड़ी स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी। युवाओं से खेती के साथ आय के अन्य साधन अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का आह्वान किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सिकल सेल एनीमिया की जांच, बचाव और उपचार के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी स्थानीय समस्याएं कलेक्टर के सामने रखीं। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए।

चीन के प्राथमिक लक्ष्य भारत पर केंद्रित न होने की वजह

चीन का उद्भव बिना तैयारी के नहीं हुआ है; यह एक सुसंगत बृहद रणनीति परिलक्षित करता है जिसका उद्देश्य समय के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को कम करना है। वह रणनीति भौगोलिक रूप से चरणों में बंटी हुई है – पहले यूरेशिया और उन समुद्री मार्गों पर ध्यान केंद्रित करना जो चीन की अर्थव्यवस्था को कायम रखते हैं, न कि सीमावर्ती ज़मीनी युद्धों पर। इसके आलोक में देखें तो भारत के साथ हिमालयी सीमा एक गौण मुद्दा है। वहां पर बड़े पैमाने का युद्ध चीन को अपने मूल उद्देश्यों में आगे बढ़ने में बहुत कम मददगार रहेगा, और असल में, नुकसानदेह हो सकता है।

चीन के आधिकारिक दस्तावेज़ प्राथमिकता के क्रम का उतना ही खुलासा करते हैं जितना छिपाकर जता जाते हैं। 'नए दौर में चीन की राष्ट्रीय रक्षा' (2019) या 'सैन्य रणनीति दिशानिर्देश, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (2015)', और एक के बाद एक आई पार्टी संसदीय रिपोर्टें सुरक्षा को शासन के अस्तित्व, तकनीकी स्वायत्तता और महा-शक्ति प्रतिस्पर्धा जैसे शब्दों में परिभाषित करती हैं। रणनीतिक दिशा स्पष्ट है – समुद्री आवाजाही मार्गों में बनने वाले जोखिम, ऊर्जा और व्यापार के पहुंच मार्गों की सुनिश्चितता और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने की क्षमता बनाना। भारत का नाम खतरे के तौर पर नहीं लिया गया है। यह कोई अनदेखी नहीं; प्राथमिकताओं का निर्धारण है।

चीन की समृद्धि समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है जो असुरक्षित 'चोकपॉइंट्स' (संकरे समुद्री रास्तों) से होकर गुज़रता है-ये मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर बृहद हिंद-प्रशांत क्षेत्र, होर्मुज़ जलडमरूमध्य और स्वेज़ नहर तक हैं। इसलिए, इसके सैन्य आधुनिकीकरण का ध्यान नौसैन्य शक्ति सुदृढ़ता, बाधित पहुंच/प्रतिबंधित क्षेत्र स्थिति का उपाय और अंतरिक्ष, साइबर एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्षमताओं पर केंद्रित है। इसके समांतर, सरकारी आर्थिक कूटनीति का उद्देश्य निर्यात में प्रभुत्व, बुनियादी ढांचा निर्माण, सपंर्क सुविधाएं और वित्तीय निवेश के माध्यम से यूरेशिया को नया रूप देना है।

आज जहां लंदन की सड़कों पर दौड़ती एक लोकप्रिय कार लैंड रोवर का सस्ता चीनी संस्करण मौजूद है वहीं जर्मनी की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। बढ़ती लागत के मद्देनज़र, सीमेंस जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन को चीन स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं, जिससे उनके वित्तीय लाभ में तो सुधार हो जाएगा, लेकिन समाज को नुकसान पहुंचेगा। यह सब यूरेशिया में समुद्र नीत और पश्चिम नीत रणनीति की ओर इशारा करता है, न कि दक्षिण-नीत हिमालय में। उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि बीजिंग किस चीज़ से बचना चाहता है – दो मोर्चों पर रणनीतिक दुविधा। उसकी मुख्य प्रतिस्पर्धा समुद्री क्षेत्र में अमेरिका के साथ है। भारत के साथ कोई बड़ा उपमहाद्वीपीय युद्ध शुरू करने से संसाधन और ध्यान बंट जाएंगे, बाहरी दखल बढ़ेगा और भारत को अमेरिका के और करीब आने का खतरा पैदा होगा- इससे वही गठबंधन विशेष मजबूत होगा, जिसे चीन कमजोर करना चाहता है। भारत के मामले में चीन की सैद्धांतिक चुप्पी का कारण डर नहीं, बल्कि समझदारी का हिस्सा है।

इसलिए, भारत को साधने के लिए चीन की नीति अपरोक्ष और किफायती तरीका अपनाती है। दशकों से, उसने व्यवस्थित रूप से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत किया -जिसमें पारंपरिक युद्धक तंत्र,मिसाइल फोर्स, परमाणु क्षमता और उपग्रह प्रदत्त सुविधाओं तक पहुंच जैसी सहायक तकनीकें शामिल हैं। इसका मकसद यह यकीनी बनाना है कि भारत अपने सुरक्षा संबंधी गुणा-भाग का दायरा दक्षिण एशिया तक ही रखे और यह सुनिश्चित करना कि भारत का ध्यान लगातार अपनी पश्चिमी सीमा पर बना रहे। इससे समुद्री क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने में भारत की क्षमता सीमित हो जाती है, जहां भूगोल उसे हिंद महासागर के अहम समुद्री मार्गों पर एक अपरोक्ष फायदा देता है-एक ऐसा लाभ जो, चरम स्थिति में, चीन की ऊर्जा जीवनरेखा और समृद्धि के लिए खतरा बन सकता है। 1962 का युद्ध पूर्व उदाहरण पेश करता है। चीन ने सीमित राजनीतिक लक्ष्य हासिल किए और फिर एकतरफा तौर पर पीछे हट गया। सार्वजनिक किए गए सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि युद्ध से छह महीने पहले माओ ने अपने सेना कमांडर को बुलाकर चार शब्दीय निर्देश दिया था: 'भारत को सबक सिखाओ'। सबक क्या था? माना जाता है, 'कन्फ्यूशियस संहिता' के अनुसार भारत को उसकी 'जगह दिखाना', न कि इलाके पर कब्जा। आज, लद्दाख जैसे इलाकों में, चीन पहले से ही उस जमीन पर नियंत्रण रखे हुए है, जिसे वह रणनीतिक रूप से अहम मानता है। प्रभुत्व बनाने का सिद्धांत हिमालयी सीमा पर और बड़े पैमाने पर इलाके पर कब्जे की जरूरत का संकेतक नहीं है।

मौजूदा भंगिमाएं निरंतर इस नजरिए को दर्शाती हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 'स्थानीय युद्ध' जैसी स्थिति में सीमित, फुर्तीले और कम समय तक चलने वाले टकराव की तैयारी कर रही है-जिसका मकसद बातचीत के दौरान दबाव बनाना, लड़ाई रोकना और अपनी शर्तों पर बातचीत करवाना है। तिब्बत में बुनियादी ढांचा निर्माण और समय-समय पर आमने-सामने की स्थिति पैदा करना मोल-भाव करने की ताकत को बढ़ाता है। बाकी सभी देशों के उलट, चीन की युद्ध संबंधी मुख्य रणनीति विरोधी को धोखे में रखना है। भारत की ज़मीन में घुसपैठ का खतरा भी ठीक इसी रणनीति का हिस्सा है। यूरेशिया से बाहर चीन के अनुभव ने उसकी सावधानी को और बढ़ाया है। लैटिन अमेरिका, खासकर वेनेजुएला जैसे इलाकों में कदम रखने से उन्हें पता चला कि अमेरिका के पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा दखल के क्या खतरे हो सकते हैं। आर्थिक जोखिम और राजनीतिक अस्थिरता ने उन्हें एक सरल सबक सिखाया है-बृहद वैश्विक मुकाबलों के बारे में सोचने से पहले यूरेशिया और आस-पास के समुद्रों में अपना प्रभाव पुख्ता करो। अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने की उनकी योजना इसलिए चरणों में बंटी हुई और सीमित है।

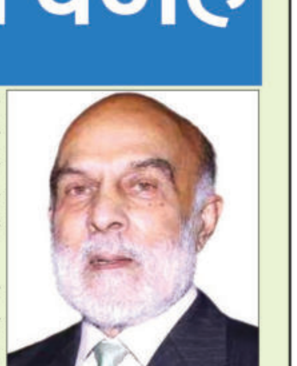

रियर एडमिरल राजा मेनन

हिमालय में फुल स्केल वॉर इस तर्क के उलट जाता है। इससे आर्थिक स्थिरता बिगड़ेगी, टकराव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाएगा और बाहरी ताकतों के इसमें शामिल होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे यूरेशिया में स्थिरता लाने वाली आर्थिक ताकत के तौर पर चीन ने अपनी जो छवि बहुत मेहनत से बनाई है, उसे नुकसान पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रतिद्वंद्विता के मुख्य मंच-यानी समुद्री और तकनीकी प्रतिस्पर्धा, जो इक्कीसवीं सदी में ताकत का संतुलन तय करेगी-उससे ध्यान भटक जाएगा। बीजिंग की ज़मीनी रणनीति यह है कि हथियारों से लैस पाकिस्तान के ज़रिए भारत को उलझाए रखो और भारत को समुद्री ताकत के तौर पर मज़बूत होने से रोको। निष्कर्ष सीधा है। चीन एक बृहद रणनीति सोचे हुए है और वह अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अनुशासित है। वह उन जगहों पर ध्यान साधकर करके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्वरूप बदलना चाहता है जहां दांव सबसे बड़ा है – यूरेशिया और समुद्री क्षेत्र। इस योजना के अंदर, भारत एक ऐसा अवयव है जिसे काबू में रखना और संभालना है, न कि मुख्य दुश्मन।

हिमालयी क्षेत्र में युद्ध चीन को अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाएगा। अंतिम विश्लेषण में, बृहद मुकाबले वाले परिदृश्य में उसके लिए यह कम ध्यान देने योग्य मुद्दा है।

उम्मीदों की पटरी : 18 वर्ष बाद आई वह सुबह

माही की गूंज, धार।

आदिवासी अंचल के लिए रेल अब सपना नहीं, हकीकत बन गई है। वर्षों से रेल सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे धार जिले की धरती पर मंगलवार को पहली बार नियमित यात्री रेल पहुंची। वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आभासी माध्यम से प्रतापनगर से धार जिले के टांडा रोड के बीच चलने वाली 12 कोच की मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

इसके साथ ही छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत जोबट-टांडा रोड रेलखंड का लोकार्पण हुआ। इससे धार और आलीराजपुर के आदिवासी अंचल का गुजरात से सीधा रेल संपर्क शुरू हो गया। धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया था। करीब 18 साल सात महीने बाद परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यात्री सेवा के लिए तैयार हुआ।

टांडा रोड पर उत्सव, आंखों के सामने पूरा हुआ सपना

प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाते ही टांडा रोड स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल हो गया। स्टेशन को सजाया गया था और ट्रेन देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। ट्रेन के रवाना होते ही लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। कई बुजुर्गों के लिए यह केवल नई रेल सेवा नहीं, बल्कि वर्षों से देखे जा रहे उस सपने का पूरा होना था, जिसके लिए इस क्षेत्र में लंबे समय से मांग उठती रही।

नई मेमू सेवा प्रतापनगर से सुबह रवाना होकर टांडा रोड पहुंचेगी और शाम को टांडा रोड से वापस प्रतापनगर जाएगी। मार्ग में वडोदरा क्षेत्र के स्टेशनों के अलावा छोटा उदयपुर, आलीराजपुर, जोबट और टांडा रोड जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं। इससे आदिवासी अंचल के लोगों को गुजरात के बड़े शहरों और व्यापारिक केंद्रों तक पहुंचने का सीधा साधन मिलेगा।

गुजरात की राह आसान

टांडा रोड से शुरू हुई यात्री रेल सेवा से गुजरात जाने वाले श्रमिकों के साथ शिक्षा, उपचार, व्यापार और रोजगार के लिए आवागमन करने वाले लोगों को सस्ता और सुगम विकल्प मिलेगा।

धार अभी बाकी, 2027 में पूरा होने की उम्मीद

टांडा रोड तक रेल पहुंच गई है, लेकिन जिला मुख्यालय धार अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। टांडा रोड से धार तक का शेष रेलखंड पूरा होने के बाद ही यह सपना पूरा होगा। परियोजना के शेष हिस्से का काम जारी है। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार टांडा रोड-धार रेलखंड को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पीढ़ियों के इंतजार के बाद पहला पड़ाव

टांडा रोड तक रेल पहुंचना अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि धार के सीधे रेल संपर्क की दिशा में बड़ा कदम है। अब क्षेत्र की अगली उम्मीद धार तक रेल पहुंचने पर टिकी है।

प्रधानमंत्री ने किया डेकाकुंड रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शुभारंभ

माही की गूंज, आलीराजपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए उनका उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसी क्रम में उन्होंने आलीराजपुर जिले के डेकाकुंड रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही जोबट-टांडा रोड रेल लाइन एवं डेकाकुंड रेलवे स्टेशन क्षेत्रवासियों को समर्पित की।

डेकाकुंड रेलवे स्टेशन के प्रारंभ होने से आलीराजपुर जिले के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल को रेल सुविधा से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से क्षेत्र के नागरिकों के लिए आवागमन सुगम होगा तथा व्यापार, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंच को भी बढ़ावा मिलेगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान ने कहा कि डेकाकुंड रेलवे स्टेशन के शुभारंभ से आलीराजपुर जिले के नागरिकों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। रेल सुविधा के विस्तार से क्षेत्र में व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे तथा विद्यार्थियों और आम नागरिकों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से जिले के दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास को भी नई गति मिलेगी।

डेकाकुंड रेलवे स्टेशन के शुभारंभ के बाद सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर एवं पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह ने नवीन ट्रेन से डेकाकुंड से आलीराजपुर तक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में बैठे यात्रियों से संवाद किया और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए।

इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणजन भी नवीन ट्रेन से यात्रा करने पहुंचे। कार्यक्रम में जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनोज गरवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर लापरवाही

माही की गूंज, धार।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निसरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित जांच शिविर के दौरान अस्पताल में मरीजों को लगाई जा रही बोतलों में ऐसी आईवी का इस्तेमाल सामने आया, जिसकी एक्सपायरी मई 2026 में ही हो चुकी थी। सुबह 11 बजे तक ऐसी एक्सपायरी आईवी से चार गर्भवती महिलाओं को बोतल चढ़ाई जा चुकी थी।

टीम बुधवार सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के साथ अन्य भर्ती मरीजों को भी बोतल चढ़ाई जा रही थी। इन बोतलों में इस्तेमाल की जा रही आईवी पर निर्माण की तारीख जून 2023 और एक्सपायरी मई 2026 अंकित थी यानी एक्सपायरी के करीब चार महीने बाद भी इसका इस्तेमाल मरीजों के उपचार में किया जा रहा था।

पूछताछ होते ही सामग्री समेटने लगे कर्मचारी

मौके पर करीब दो थैलियां भरी हुई आईवी तथा बड़ी संख्या में अन्य एक्सपायरी आईवी रखी हुई दिखाई दीं। जब मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों से एक्सपायरी आइवी के इस्तेमाल को लेकर सवाल किया गया तो कुछ ही देर में कर्मचारी इन्हें समेटते नजर आए। बताया गया कि सामग्री को थैलियों में भरकर वहां से बाहर ले जाया गया। इससे अस्पताल में दवाइयों और चिकित्सा सामग्री के रखरखाव तथा नियमित जांच की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

कई दिनों से इस्तेमाल का दावा

मौके पर मिली जानकारी के अनुसार एक्सपायरी आईवी का इस्तेमाल बुधवार से ही नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक कितने मरीजों को एक्सपायरी आईवी लगाई जा चुकी है। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि इसके इस्तेमाल के बाद किसी मरीज को संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य समस्या तो नहीं हुई।

हर 8-10 दिन में निरीक्षण का दावा, फिर कैसे छूटी एक्सपायरी सामग्री?

स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों का नियमित निरीक्षण किए जाने की बात कही जाती है। कई बार यह भी बताया जाता है कि अस्पताल में करीब 8-10 दिन के अंतराल में दवाइयों और उपकरणों की जांच की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि मई 2026 में एक्सपायर हो चुकी आईवी कई दिनों तक अस्पताल में मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होती रही और नियमित निरीक्षण में यह मामला पकड़ में क्यों नहीं आया?

क्या है आइवी और क्यों जरूरी है सावधानी?

अस्पतालों में मरीज को बोतल या दवा चढ़ाने के लिए जिस प्लास्टिक की नली और उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसे आमतौर पर आइवी सेट कहा जाता है। इसी माध्यम से दवा या तरल मरीज के शरीर तक पहुंचता है। इसलिए इसकी गुणवत्ता और एक्सपायरी की जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक्सपायरी चिकित्सा सामग्री के इस्तेमाल से संक्रमण सहित अन्य जटिलताओं का जोखिम हो सकता है। हालांकि इस मामले में मरीजों को वास्तव में किसी तरह का संक्रमण हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि चिकित्सकीय जांच के बाद ही हो सकेगी।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत वितरण कैंप का आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

समाज के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत जनपद पंचायत चन्द्रशेखर आजाद नगर में वितरण कैंप का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। योजना के माध्यम से वरिष्ठजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनके दैनिक जीवन को सरल, सुविधाजनक एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

वितरण कैंप में पूर्व में चिन्हांकित पात्र वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण एवं जीवनोपयोगी सामग्री वितरित की गई। इनमें मुख्य रूप से व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, श्रवण यंत्र, कृत्रिम दांत एवं अन्य आवश्यक सहायक उपकरण शामिल रहे। कैंप में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने सहभागिता कर योजना का लाभ प्राप्त किया। लाभार्थियों ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस महत्वपूर्ण सुविधा के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया।

इस दौरान जोबट विधायक श्रीमती सेना पटेल ,जनपद पंचायत अध्यक्ष जगदीश गणावा, पूर्व विधायक माधोसिंह डावर, जनपद पंचायत सीईओ इंद्रसिंह पटेल सहित जनप्रतिनिधि एवं सरपंच उपस्थित रहे।

बस में 46 बच्चों की जान बचाकर ड्राइवर ने तोड़ा दम

माही की गूंज, धार/बाग।

महेश मेमोरियल स्कूल बाग की बस सोमवार को 46 बच्चों को लेकर जोबट जा रही थी। इसी दौरान झिरपन्या के पास अचानक बस चालक 57 वर्षीय कन्हैयालाल बघेल की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें घबराहट की शिकायत हुई। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने सूझबूझ दिखाई और चलती बस को तत्काल सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया। उनकी इस सतर्कता से बस में सवार 46 बच्चों की जान जोखिम में पड़ने से बच गई। हालांकि कुछ देर बाद अस्पताल में कन्हैयालाल ने दम तोड़ दिया।

कन्हैयालाल बघेल ग्राम देंगाव भीलखेड़ी तहसील जोबट के निवासी थे और महेश मेमोरियल स्कूल की बस चला रहे थे। स्कूल प्राचार्य सुरेंद्रसिंह चौहान के अनुसार सोमवार को दिनभर कन्हैयालाल सामान्य थे। दोपहर करीब ढाई बजे भी उन्होंने स्कूल स्टाफ से बातचीत की थी। शाम को बच्चों को लेकर बस झिरपन्या के पास पहुंची, तभी अचानक उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ।

तबीयत बिगड़ने पर कन्हैयालाल ने सबसे पहले बस को सड़क किनारे लगाया और उल्टी की। इसके बाद वे बस चलाने की स्थिति में नहीं थे। कंडक्टर ने उन्हें ड्राइवर सीट से हटाकर कंडक्टर सीट पर बैठाया और तत्काल स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंचा।

झिरपन्या में मौजूद एक अन्य चालक को भी बुलाया गया। उसने तत्काल बच्चों से भरी बस की कमान संभाली और सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से जोबट अस्पताल पहुंचाया। वहीं कन्हैयालाल को भी बस में कंडक्टर की सीट पर बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अंतिम समय तक बच्चों की सुरक्षा का रखा ध्यान

प्राचार्य सुरेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि कन्हैयालाल ने अंतिम समय में भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। चलती बस में अचानक तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने बिना घबराए बस को तत्काल सड़क किनारे रोक दिया। यदि उन्होंने समय रहते बस नहीं रोकी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में छोटे बच्चों से लेकर कक्षा 12वीं तक के कुल 46 बच्चे सवार थे। चालक की सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित रहे, लेकिन बच्चों की जान बचाने वाले कन्हैयालाल खुद जिंदगी की जंग हार गए। घटना के बाद विद्यालय परिवार में शोक की लहर है। शोक स्वरूप विद्यालय में मंगलवार को अवकाश रखा गया।

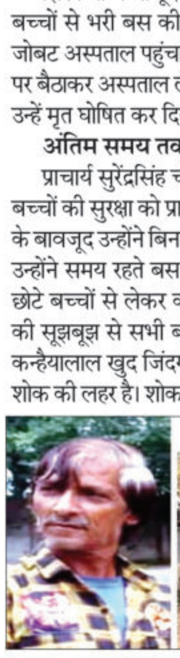

हर-हर महादेव से शुरू होता है अनुष्ठान का गायना

माही की गूंज, अलीराजपुर।

भील एवं मालवा अंचल की समृद्ध जनजातीय एवं लोक परंपराओं, अनुष्ठानों तथा उनसे जुड़ी सांस्कृतिक स्मृतियों को समझने, संरक्षित करने और दस्तावेजीकृत करने के उद्देश्य से 08 एवं 09 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, क्रांतिकारी शहीद छितुसिंह किराड़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर के सभागार में दो दिवसीय परिसंवाद का शुभारंभ हुआ।

परिसंवाद का केंद्रीय विषय ÷चौमासे के जनजातीय एवं लोक अनुष्ठान ः सांस्कृतिक स्मृति और अभिप्राय÷ है। आयोजन में विशेष रूप से भील एवं मालवा अंचल की लोक-सांस्कृतिक परंपराओं, अनुष्ठानों, लोकविश्वासों तथा उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षों पर केंद्रित विमर्श हुआ। यह आयोजन जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, क्रांतिकारी शहीद छितुसिंह किराड़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर के सहयोग से किया जा रहा है।

परिसंवाद के संबंध में जानकारी देते हुए निदेशक डॉ. पारे ने कहा कि किसी एक स्थान पर एकत्र होकर किसी लोक देवी-देवता का किसी उद्देश्य से पूजन किया जाना अनुष्ठान कहलाता है। इन अनुष्ठानों को केवल जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके पीछे निहित चेतना और सांस्कृतिक भाव को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ÷जब भी जीवन में सुख आए तो उसे बांटकर खाना चाहिए और दुःख आए तो उसे अकेले सहना चाहिए– यही जनजातीय संस्कृति की विशेषता है।÷

महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. मीना सोलंकी ने अकादमी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक इन अनुष्ठानों के नाम ही सुने थे, लेकिन आज उन्हें प्रत्यक्ष और जीवंत रूप में देखकर जनजातीय संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिल रहा है। इससे विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

वक्ता कादू सिंह डुडवे ने भीली समुदाय में वनस्पतियों से जुड़े विश्वासों और पारंपरिक ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भाजियां पाई जाती हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और पोषक होती हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय समुदाय इन वनस्पतियों के गुणों और उपयोगों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी संजोकर रखता आया है।

वक्ता सुश्री श्वेता ने भीली पिठोरा का रंगीन चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति को पूजनीय मानता है। उन्होंने बताया कि पिठोरा अनुष्ठान तीन दिनों तक चलता है। पहले दिन गायना होता है, दूसरे दिन पिठोरा का समग्र चित्रण किया जाता है तथा अंतिम दिन सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित कर पारंपरिक पूजा-अनुष्ठान संपन्न किया जाता है।

वक्ता सुश्री मनीषा ने भील-भिलाला समाज में बांस के सदुपयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बांस का उपयोग अनेक अनुष्ठानों, रीति-रिवाजों तथा दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बांस जनजातीय जीवन और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परिसंवाद की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र कुमार बारिआ ने चौमासा के अनुष्ठानों में जातर अनुष्ठान के महत्व पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भील समाज में कुछ अनुष्ठान सामूहिक रूप से संपन्न होते हैं, जबकि कुछ अनुष्ठान परिवार एवं घर की परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों में सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक स्मृति का विशेष महत्व है।

'दिवासा' की गायना प्रस्तुति ने किया भावविभोर

दिवासा अनुष्ठान की सामूहिक गायना प्रस्तुति देते हुए बहादुर वेया ने बताया कि बाबा देव की आराधना के लिए दिवासा अनुष्ठान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसका गायना ÷हर-हर महादेव÷ के उद्घोष से प्रारंभ होता है और अंत में पुरखों की स्मृति के साथ इसका समापन होता है। प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने अनुष्ठान की सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक भाव को ढाक वादन से जीवंत किया।

'गाज माता' अनुष्ठन की संगीतमय प्रस्तुति

मालवा की लोक संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए श्रीमती पूर्णिमा जी ने समूह के साथ गाज माता अनुष्ठान की संगीतमय प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में राजा, रानी और भिलनी रानी के साथ गाज माता के पात्रों का प्रभावशाली अभिनय रहा, जिसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। पारंपरिक गायन, अभिनय और लोक-अभिव्यक्ति के समन्वय ने मालवा की जीवंत लोक-सांस्कृतिक परंपरा का परिचय कराया।

कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करते हुए डॉ. सज्जन सिंह मौर्य ने कहा कि महाविद्यालय में इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी लोक एवं जनजातीय संस्कृति को करीब से जान और समझ सकें। उन्होंने कहा कि मालवा की सांस्कृतिक पहचान यहां की समृद्ध वनस्पतियों, लोक परंपराओं और जनजातीय अनुष्ठानों से गहराई से जुड़ी हुई है। जनजातीय समाज ने बदलते समय और आधुनिक जीवनशैली के बीच भी अपनी परंपराओं एवं अनुष्ठानों की मूल पहचान को बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन इन जीवंत परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनजातीय प्रदर्शनी में दिखी समृद्ध सांस्कृतिक की विरासत

परिसंवाद के साथ महाविद्यालय परिसर में जनजातीय प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें भील एवं भिलाला समाज की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में पारंपरिक भीली आभूषणों, स्थानीय वनस्पतियों, भाजियों एवं पारंपरिक व्यंजनों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से जनजातीय समाज के पारंपरिक जीवन, खान-पान, प्रकृति से जुड़ाव और भीली चित्रों की झलक देखने को मिली। विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर जनजातीय जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पक्षों को करीब से जाना। उक्त जानकारी संस्कृति विभाग द्वारा दी गई।

कलेक्टर का आश्वासन मेघनगर क्षेत्र की जनता के लिए गीला और ठंडा पोछा भर तो नहीं...?

समस्या का समाधान ना होने पर प्रदर्शनकारियों की फिर से लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी भी...

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसूरी

24 अक्टूबर 1984 यह वह तारीख है जब मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी बाहुल जिले झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तत्समय औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से जिलेवासियों में हर्ष का माहौल था। लोगों को इस औद्योगिक क्षेत्र से कई उम्मीदें थी। जिले के मेघनगर में स्थित इस औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 223.75 हेक्टेयर है और इसे एमपी एकेवीएन इंदौर (मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र उद्योग विकास निगम) इंदौर द्वारा विकसित किया गया था। लोगों में इसे लेकर उत्साह भी था कि, अब जिले में रोजगार के अवसर खुलेंगे और जिला विकास की राह पर दौड़ेगा। लेकिन उस समय मेघनगर क्षेत्रवासियों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि, यह औद्योगिक क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप...? औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के बावजूद इस क्षेत्र में वर्षों औद्योगिक ईकाइयों की भारी कमी रही इसके अपने अलग-अलग कारण है। जैसे-जैसे समय बीतता गया लोगों में इसे लेकर निराशा ही देखने को मिली। क्योंकि बड़े उद्योगपतियों ने इस औद्योगिक क्षेत्र को इस लायक नहीं समझा कि, यहां औद्योगिक ईकाईयां लगाई जा सके। इस चरमराई स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी तरह चिंतित भी दिखाई दी। गुजरते समय के साथ वह दिन भी आया जब इस औद्योगिक क्षेत्र में धीरे-धीरे औद्योगिक ईकाईयां आने लगी। तब भी क्षेत्रवासियों को यह अंदाजा नहीं था कि, यह उनके लिए लाभप्रद होगी या हानीकारक...?

चूंकि मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसा होने के कारण यहां जिले से तीन प्रदेशों की सीमाएं लगती थी। जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात है। यही वह कारण भी बना जिसने मेघनगरवासियों की जीवन शैली पर गहरा आघात किया। देखते ही देखते गुजरात के कई उद्योगपतियों ने मेघनगर में अपने औद्योग लगाने शुरू कर दिए। जब राजनीतिक हलकों में यह मामला गर्माया तो एक बड़ा ही चौकाने वाला सच सामने आने लगा जिसने हर किसी को चौका दिया। सुत्रों के अनुसार यहां की अधिकांश केमिकल फैक्ट्रियों के मालिक गुजरात के उद्योगपति और राजनीतिज्ञ थे, जिन्हे गुजरात में प्रदूषण नियमों की सख्ती के बाद प्रतिबंधित किया गया। बाद में उन्ही उद्योगपतियों ने मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किया। तत्कालीन समय में यह मुद्दा बहुत तेजी से गर्माया था। तब से लेकर अब तक लगातार मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में लगातार स्वर गूंजते रहे है। कांग्रेसी नेताओं ने मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाए थे कि, गुजरात से हटाई गई या प्रतिबंधित की गई इन फैक्ट्रियों के कारण मेघनगर क्षेत्र में भयंकर जल और बायु प्रदूषण फैल रहा है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले लाल और एसिडिक केमिकल युक्त पानी से आसपास के दर्जनों गांवों का भूजल दूषित हो चुका है, फसलें बर्बाद हो रही है और मवेशियों की मौत भी हुई है।

मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में लगी प्रदूषण फैलाने वाली इन फैक्ट्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भी अब वर्षों नहीं दशकों हो चुके है। इसे सरकार और तंत्र का निकम्मापन ही कहा जाएगा कि, मेघनगर क्षेत्र में उपज रहे प्रदूषण के खतरे को सरकार और तंत्र अब भी हलके में ही ले रही है और स्थितियां अब भी गंभीर से गंभीर होती जा रही है। क्योंकि अब इन प्रदुषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों का दुष्प्रभाव यहां मानव जीवन शैली पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही है तो स्वांस संबंधी रोगों में भी इजाफा देखने को मिला है।

इन सारी समस्याओं को लेकर मेघनगर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले एक पखवाड़े से आमजन मानस में विरोध के स्वर गूंज रहे थे। 31 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर एक आव्हान सामने आया जिसमें 8 सितम्बर को औद्योगिक क्षेत्र से हो रहे जलवायु प्रदुषण के खिलाफ मेघनगर से झाबुआ तक पैदल मार्च का आव्हान किया गया। इस खबर के सामने आते ही प्रशासनिक बौखलाहट भी ताबड़तोड़ देखने को मिली। नेतृत्व के अभाव में पैदल मार्च आयोजन को प्रशासन ने स्वीकृति नहीं दी। जबकि आयोजकों का कहना था कि यह आयोजन सर्वसमाज कर रहा है।

इसके पहले कि यह आंदोलन कोई बड़ा रूप लेता प्रशासन ताबड़तोड़ हरकत में आ गया और हर उस योजना को अपनाया गया जिससे इस आंदोलन को रोका या ठंडा किया जा सके। इसी कड़ी में पहले मेघनगर प्रशासनिक अमले ने औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसके बाद लगातार जिला प्रशासन और कलेक्टर ने भी मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र की दौड़ लगाना शुरू की। नतीजा यह निकला कि, आंदोलन में कुछ हो पाता उसके पहले ही चतुर प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र की पांच ईकाईयों को सील कर दिया। ऐसा करके प्रशासन ने आंदोलन की रीढ़ ही तोड़ दी। अब सवाल यह है कि, जो काम प्रशासन ने अब किया वह पहले क्यों नहीं हो सकता था...? जबकि मेघनगरवासियों की औद्योगिक क्षेत्र से होने वाले प्रदुषण की शिकायत तो बरसों पुरानी है...! पांच फैक्ट्रियों को सील करने के बाद भी शायद प्रशासन को शंका थी कि, आंदोलनकारी जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रोरेट का घैराव करेंगे तो प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी। और इसी बीच यह सरकारी समाचार भी जारी कर दिया कि 8 सितम्बर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई जिला मुख्यालय पर ना होकर मेघनगर विकासखंड में होगी। कलेक्टर और प्रशासननिक यह कदम बहुत ही चतुराई भरा साबित हुआ। या यूं कहलें कि जिला प्रशासन और कलेक्टर ने मिलकर मेघनगरवासियों के आक्रोश पर गीला व ठंडा पोछा फैर दिया।

इस आंदोलन की हवा निकालने के बाद कलेक्टर ने मेघनगर विकासखंड में जनसुनवाई ली और इस जन सुनवाई में फुटतालाब से मेघनगर तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च कर पहुंचे लोगों से चर्चा की। चर्चा में कलेक्टर ने प्रमुख चार मांगों पर आंदोलन कारियों को आश्वासन का झुनझुना पकड़ा दिया। हालांकि कलेक्टर ने यह माना कि, मेघनगर और आसपास के क्षेत्रवासियों की यह समस्या बहुत पुरानी है। कलेक्टर ने कहा कि, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर कार्रवाई करता रहा है। हाल ही में प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कई फैक्ट्रियों को सील करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि, नियमों का उल्लंघन करने और गंदा पानी बाहर छोड़ने वाली पांच फैक्ट्रियों को हाल ही में सील कर दिया गया है। सवाल यह कि, आखिर यह नौबत अब ही क्यों आई, प्रशासन पहले कौन सी नींद में सो रहा था। अगर नियमों की बात करें तो वर्तमान में मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के लिए लागू मुख्य गाइडलाइंन और प्रशासनिक नियम के अनुसार शून्य तरल निर्वहन का कड़ा पालन केमिकल और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित और एसिडिक पानी को किसी भी हालत में खुले में, खेतों में या स्थानीय नदी-नालों में बहाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। तो फिर अब तक क्षेत्रवासियों की शिकायत के बावजूद इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया...?

क्यों इस समस्या को इस कदर बढ़ने दिया गया कि अब लोगों का जीना ही मुहाल हो रहा है...?

क्यों प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने कर्तव्य का निर्वहन समस्या उपजने से पहले नहीं किया...?

लगातार शिकायतों के बावजूद एमपी एकेवीएन क्यों अपनी आंखों पर पट्टी और कानों में रूई डाले रहा...? शिकायतें तो वर्षों पुरानी है तो फिर जिला प्रशासन ने इस पर तत्परता दिखाने में क्यों रूची नहीं ली...?

अब जिला प्रशासन की नींद जब मेघनगरवासियों के आंदोलन की हुकार से खुली तब कलेक्टर के मुंह से यह निकल रहा है कि, औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे प्रदुषण और अन्य संदेहास्पद ईकाईयों की निगरानी की जाएगी। जबकि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के 2026 के नए नियमों के तहत उद्योगों को प्रदूषण मानकों का पालन करने के लिए रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स से नियमित साइट वेरिफिकेशन और कंप्लायंस असेसमेंट कराना अनिवार्य है। फैक्ट्रियों के धुंए और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियमों को कड़ा किया गया है।

कलेक्टर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से कहा कि, स्थानीय प्रदूषण की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए प्रशासन ने अधिकारियों, पुलिस, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय ग्रामीणों या जनप्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई है। यह समिति फैक्ट्रियों के प्रदूषण स्तर की निगरानी करेगी।

कुल मिलाकर फिलहाल प्रशासन और कलेक्टर ने मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से परेशान क्षेत्रवासियों को आश्वासन का पुलिंदा थमाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन अब आगे समय ही बताएगा कि, कलेक्टर का यह आश्वासन आमजन के हित में कितना जमीन पर उतर पाएगा...? क्योंकि मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से उपज रहे जलवायु प्रदूषण की शिकायत कोई नई नहीं है। मेघनगर व आसपास के क्षेत्रवासी वर्षों से इस समस्या से दो-चार हो रहे है। ऐसा भी नहीं है कि, यह कोई पहली शिकायत है...? इससे पहले भी लोगों ने कई जिला अधिकारियों को इसकी शिकायत की है। ऐसा भी नहीं है कि, कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसट का यह पहला आश्वासन है, इससे पहले भी कई कलेक्टर मेघनगरवासियों को ऐसे आश्वासन दे चुके है। लेकिन मेघनगरवासियों की समस्या का समाधान अब तक उनके पास नहीं पहुंचा है।

अब मेघनगरवासियों की कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसट के आश्वासन पर नजर है। यह समय ही बताएगा कि, कलेक्टर तुकाराम भरसट मेघनगरवासियों के किए वादे और आश्वासन पर कितना खरा उतरेंगे। या फिर कलेक्टर का आश्वासन मेघनगर क्षेत्र की जनता के लिए एक बार फिर गीला और ठंडा पोछा ही साबित होगा...? हालांकि समस्या के स्थाई समाधान ना होने पर प्रदर्शनकारियों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी है।

हवाला में करोड़ों की हेरा -फेरी करने वाले पटवा ने लगाया कर्मचारी पर चोरी का आरोप, कर्मचारी ने किया सुसाईड

परिजन कह रहे बेटा अमानत घर लेकर आया था न की चोरी की थी

माही की गूंज, झाबुआ/बामनिया।

कहते हैं हम किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं पर यह प्रयास कभी-कभी दोनो पक्षो के लिए बड़ा महंगा भी पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही मामला जिले के ग्राम बामनिया में सामने आया है।

मामले में सामने आया कि, बामनिया निवासी सुनील पटवा व उसका पुत्र राहुल पटवा जो कि, जिले में सबसे बड़ा रुपैयो का हवाला व्यापारी है। साथ ही अनाज के थोक खरीदी व्यापारी है, साथ ही वेयरहाउस होकर अन्य व्यापारी के अनाज का स्टॉक भरवाकर स्टॉक अनाज पर ब्याज का लेनदेन भी बड़े पैमाने पर करता है। उक्त पटवा परिवार के पास ऑफिस, खरीदी-बिक्री, वेयरहाउस एवं लेनदेन आदि हेतु करीब 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। जिसमें प्रतीक नाम का एक युवक पिछले सात-आठ वर्षो से यहा कार्य करता है। यह युवक ऑफिस कार्य के साथ खरीदी-बिक्री व बैंकों के लेनदेन का पूरा हिसाब करता हैं। तथा प्रतीक की ड्यूटी 24 घंटे होकर रात्रि में ऑफिस पर ही सोता था व रात में भी अनाज से भरे आने-जाने वाले ट्रक का अवलोकन कर हिसाब रखता था।

कहा जाता है कि, प्रतीक ने अपनी वफादारी के साथ राहुल पटवा व उसके पिता सुनील पटवा के यहां उनका कर्मचारी नहीं बल्कि घर का सदस्य के रूप में ग्राम में चर्चा होती व उसके कार्य की सराहना की जाती। यह भी तय है कि, इतने बड़े कारोबार में अपना खर्चा-पूर्ति हेतु कर्मचारी छोटी-बड़ी सेंध हिसाब-किताब में लगा देते होंगे इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां ग्राम बामनिया में युवक प्रतीक की ईमानदारी की दुहाई दी जाती थी। वहीं कहीं न कहीं यह दुहाई प्रतीक के प्रति राहुल पटवा व उसके पिता को रास नहीं आती थी।

नतीजन यह रहा कि, राहुल पटवा कहीं न कहीं प्रतीक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का मन बना चुका था और यह मन क्यो बनाया होगा यह तो वही जाने। पर इसके चलते कुछ माह पूर्व से राहुल द्वारा गांव में प्रतीक अमानत में खमानत करता है की बात का हवाला देकर चर्चा करता था। तथा इसी चर्चा के साथ यह भी कहता था कि, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए ऑफिस में आने-जाने वाले करीब चार-पांच कर्मचारियों पर 10-10 हजार रुपए नामे लिख दिए गए। यानी 50 हजार की खमानत की बात राहुल पटवा द्वारा कहीं जाती रही है।

वहीं 5 अगस्त को यह कहानी सामने आई कि, सुनील पटवा व पुत्र राहुल पटवा सुबह-सुबह ही जब प्रतीक ऑफिस से घर नहाने गया उसके बाद उसके घर आए। घर आने के पूर्व राहुल पटवा ने फोन लगाकर 1 लाख रुपए चोरी कर लेने की बात प्रतीक व उसके माता-पिता को कहीं व धमकाकर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी। लेकिन प्रतीक ने कहा मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की। वही सुनील व राहुल पटवा प्रतीक के घर पहुंचे और वहां पर भी गंदी-गंदी गालियां देते हुए धमकाया व 1 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस से अनगिनत जूते खिलवाने की धमकी देकर चले गए। वहीं प्रतीक के माता-पिता ने अपने रिश्तेदार सत्तू झिण वाले व पड़ोसी विजय को बुलाकर पूरी बात बताई। विजय व सत्तू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतीक को कार में ले गए और विश्वास दिलाकर पूछा कि, हकीकत क्या है...?

हवाला में करोड़ों की हेरा-फेरी करने वाले उक्त राहुल पटवा ने अपने पिता व दोस्त के साथ मिलकर युवक एवं परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का घृणित अपराध कर सुसाइड हेतु किया मजबूर।

तो त्वरित प्रतीक ने बताया कि, भैया मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे चोर बताने पर मेरे में डर भरा गई है, जबकि बात यह है कि, ऑफिस का पूरा हिसाब किताब लाखों रुपए का मैं रखता हूं ऐसे में मैं चोरी क्यों करूंगा...? प्रतीक ने बताया कि, 70 हजार रुपए ऑफिस में पड़े थे वह अमानत के रूप में मेरे साथ लेकर घर आया था। ऑफिस पर कोई नहीं था ऐसे में यह अमानत ऑफिस में रखना सही नहीं था। उक्त 70 हजार वापस आफिस पर जाता तो यह कलम हिसाब के साथ राहुल भाई या सुनील अंकल जी को दे देता। लेकिन मेरे घर आते ही मुझ पर अमानत के रखे 70 हजार रुपए को अब मुझ पर दोनों बाप-बेटे एक लाख रुपए की चोरी करना बता रहे हैं। ऐसे में मैं डर गया व उनके सामने भी मेरे द्वारा चोरी नहीं की गई कहा गया। तथा प्रतीक ने त्वरित 70 हजार रुपए सत्तू झिण वाले के हाथ में दे दिए तथा कहा कि, अब राहुल व सुनील पटवा के यहां मैं काम नहीं करूंगा।

वहीं सामने आ रहा है कि, सत्तू झिण वाले ने त्वरित ही राहुल पटवा को फोन लगाकर कहा कि, आपकी 70 हजार रुपए की अमानत प्रतीक लेकर आया है यह कबूल किया है और आप आकर पैसे ले जाओ।

लेकिन राहुल पटवा ने पैसे आकर लेने की बजाय पुलिस को कहा कि, प्रतीक ने पैसे कबूल कर लिए और आप चलो और प्रतीक की इज्जत खराब कर उसे चौकी लेकर आओ। पुलिस भी हवाला कारोबारी के मोह में आ गई और मय वीडियोग्राफी के प्रतीक के साथ हाथापाई कर पुलिस चौकी लेकर आई और वहां पर भी माता-पिता के कहने पर चोरी करने के आरोप लगाए व हाथापाई की गई।

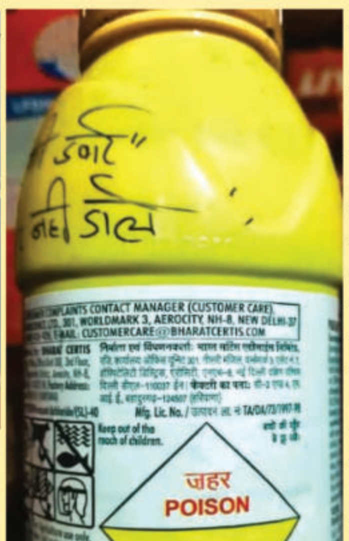

वहीं राहुल पटवा पुलिस चौकी पर सार्वजनिक कहता नजर आया कि, मुझे प्रतीक पर कई महीनो से शंका थी कि, यह चोरी करता है लेकिन पिछले 2 महीने से इस पर पूरी नजर रखी हुई थी और आज 1 लाख 70 हजार के ऊपर की रकम ऑफिस में नगदी रखी थी और उसमें से 1 लाख रुपए चोरी कर यह लाया। वहीं जब प्रतीक की मां पड़ोसी युवक के साथ राहुल के घर उनकी मोटरसाइकिल लेने गए। तो वहां भी राहुल पटवा ने सभी को चोर करते हुए कहा कि, आपके यहां आपके पति व आपका ऑपरेशन दो-दो, तीन-तीन बार हुए तो यह भी पैसा कहां से आया...? अनगर्ल आरोप लगाकर पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास राहुल पटवा ने किया।

वहीं पुलिस चौकी पर बड़ी गहमागहमी के साथ सत्तू झिण वाले ने कहा अगर वास्तविक रूपयो की चोरी की है तो आप एफआईआर दर्ज करवा दो, और यह प्रतीक अमानत के रूप में पैसे लाया है यह मानते हो तो आपका रुपया लो और मामले को खत्म करो।

जिस पर राहुल पटवा ने 1 लाख रुपए पूरे लेने की बात कही लेकिन सत्तू झिण वाले के पास प्रतीक के दिए 70 हजार रुपए ही थे ऐसे में स्थानीय जितेंद्र चौरड़िया हस्तक्षेप कर 30 हजार की गारंटी ली व नगदी 30 हजार लाकर पूरे 1 लाख रुपए लेने के बाद लिखित समझौता पुलिस को देकर राहुल अपने घर आ गया।

यह बात यहीं खत्म नहीं हुई राहुल गांव में कइयों को कहते नजर आया व गांव में चर्चा चलने लगी कि, उसे कई महीनो से शंका थी दो माह से वह रेकी कर रहा था और आखिर वह चोर हाथ में आ गया और गांव में इसकी इज्जत खराब कर दी और यह चर्चा गांव के चौराहे की चर्चा बन गई। ऐसे में प्रतीक ने अपनी एवं परिवार की प्रतिष्ठा को राहुल पटवा, उसके दोस्त बब्बू (शुभम) गांधी व सुनिल पटवा ने धूमिल कर दी यह मान लिया और 6 अगस्त रात्रि में अत्यधिक जहरीली कीटनाशक चारा नष्ट करने वाली दवाई कहीं से खरीद कर लाया और देर शाम को ही पीकर अपने दोस्तों को दवाई की सीसी व्हाट्सएप पर सेंड कर अलविदा कहा।

जिस पर दोस्तों ने त्वरित सत्तू झिण वाले को सूचना दी। जिसके बाद सत्तू झिण वाले व उसके सेठ मोहन अग्रवाल दोनों इस तरीके के कदम नहीं उठाने की समझाइए घर जाकर दी लेकिन प्रतीक ने यह नहीं बताया कि उसने दवाई पी ली थी।

अलसुबह जब प्रतीक की तबीयत बिगड़ती दिखी तो बामनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से रतलाम रेफर कर दिया गया। बताते हैं उक्त चारा दवाई पीने वाला कोई व्यक्ति बचता नहीं है अगर कम दवाई पी है तो 1 से 2 प्रतिशत चांस बचने के है। वही रतलाम डॉक्टर के. के. शाह ने भी अन्य बड़े अस्पताल में ले जाने का कह दिया।

गांव में चर्चा चल रही है कि, अमानत का पैसा था और अगर पैसा लेकर ही समझौता करना था तो राहुल पटवा को पुलिस का सहारा नहीं लेना था। और अगर वास्तविक उसके पैसों की चोरी हुई थी तो मामला दर्ज करवाना था। लेकिन अमानत के रूप में रखे पैसों को चोरी होना बताकर वह भी 70 हजार के बदले 1 लाख रुपए लेकर परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का घृणित अपराध कर समझौते का ढोंग किया जो कहीं भी सही नहीं है।

वही चर्चा है कि, माता-पिता की गरीब स्थिति के साथ प्रतीक के स्वास्थ्य व अपने घर के चिराग को तिल-तिल खोते देख रो-रोकर बेहाल हो गए हैं। देखना है पटवा परिवार आगे इस मामले को क्या रूप देते हैं और किस दिशा में ले जाते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422